

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

“छोटी दूरी हो या लंबा सफर, रेल यात्रा को बनाइए बेहतर विकल्प। कम होगा ईंधन खर्च, मजबूत बनेगा देश का भविष्य।”

“रेल का साथ चुनिए, ईंधन संकट को दूर कीजिए। अपने हर सफर को राष्ट्रहित से जोड़ दीजिए।”

वर्ष-36 अंक:09-10 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 01-31 मई 2026 (सयुक्तांक) पृष्ठ 12, मूल्य:20 रु. मात्र डाक खर्च (रंगीन सहित)

रेल विकास की पटरी पर दौड़ेगा नया भारत केंद्र सरकार ने स्वीकृत की 3 मेगा मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं



सूत्र/रे.स.ब्यू - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की लगभग 23,437 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी। इन परियोजनाओं में नागदा-मथुरा तीसरी और चौथी लाइन, गुंतकल-वाडी तीसरी और चौथी लाइन, बुरहवाल-सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। रेल लाइन की क्षमता में वृद्धि से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। इस बहु-ट्रैकिंग प्रस्ताव से परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नए भारत की परिकल्पना के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहु-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन परियोजनाओं से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध

आवाजाही सुनिश्चित होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 19 जिलों में फैली इन तीन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर तक की वृद्धि होगी।

प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 4,161 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 83 लाख है। प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से महाकालेश्वर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मथुरा, वृंदावन, मंत्रालयम (श्री राघवेंद्र स्वामी मठ), श्री नेटिकंती अंजनेय स्वामी वारी मंदिर (कासापुरम), श्यामनाथ मंदिर, नैमिषारण्य (नीमसर) आदि सहित देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा।

प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, तेल, लोहा और इस्पात, लौह अयस्क, कंटेनर, उर्वरक आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष

- 6 राज्यों के 19 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा
- रेलवे नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर की वृद्धि
- कनेक्टिविटी, क्षमता और संचालन में आएगा बड़ा बदलाव



लगभग 60 मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में सहायता करेगी, तेल आयात (37 करोड़ लीटर) को कम करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (185 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा, जो 7 करोड़ पौधारोपण के बराबर है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना में रेल अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 मई 2026 को तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ की प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को मजबूत करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और यात्रियों व माल की आवाजाही को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये परियोजनाएं भारतीय रेल के उन लगातार प्रयासों का हिस्सा हैं जिनका उद्देश्य महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर को आधुनिक बनाना, भीड़भाड़ वाले खंडों को भीड़-मुक्त करना और यात्रियों को तेज, सुरक्षित व अधिक विश्वसनीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

इन परियोजनाओं का एक प्रमुख घटक काजीपेट-विजयवाड़ा मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना के कई खंड हैं, जो 118 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इनमें वारंगल-काजीपेट, नेकोंडा-महबूबाबाद और एरुपालेम-डोर्नकल जंक्शन रेल खंड शामिल हैं। इस परियोजना से तेलंगाना के हनुमकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जैसे प्रमुख जिलों को फायदा होगा। यह कॉरिडोर व्यस्त 'ग्रैंड ट्रंक' मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण यात्री और माल यातायात को संभालता है।

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लाइन की क्षमता में काफी वृद्धि करेगी। इससे रेलगाड़ियों का परिचालन अधिक सुचारु और तेज हो सकेगा। इसके साथ ही अधिक उपयोग वाले मार्गों पर भीड़ भी कम होगी। इससे रेलगाड़ियों के समय की पाबंदी में सुधार होने, मालगाड़ियों के ठहराव में कमी आने और पूरे क्षेत्र में माल की अधिक कुशल आवाजाही संभव होने की आशा है।

इस परियोजना से विशेष रूप से उन यात्रियों को फायदा होगा जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व उत्तरी भारत के प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा करते हैं। इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी, देरी कम होगी और काजीपेट-विजयवाड़ा कॉरिडोर के माध्यम से तेज आवागमन संभव हो सकेगा।



माल ढुलाई क्षमता बढ़ने से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कोयला, सीमेंट, उर्वरक, कृषि उपज और औद्योगिक सामानों के परिवहन में भी सहायता मिलेगी। इससे तेज और ज्यादा कुशल लॉजिस्टिक्स आवाजाही के जरिए स्थानीय उद्योगों, किसानों और व्यवसायों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री 21 किलोमीटर लंबा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के सबसे व्यस्त रेल जंक्शनों में से एक, काजीपेट जंक्शन पर भीड़भाड़ को कम करना है।

यह बाईपास हैदराबाद, बल्हारशाह और विजयवाड़ा की ओर रेलगाड़ियों की एक साथ आवाजाही को संभव बनाएगा। इससे परिचालन में लचीलापन

काफी बढ़ जाएगा और रेलगाड़ियों का प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा। यह परियोजना इस व्यस्त जंक्शन पर परिचालन संबंधी टकरावों और क्रॉसिंग में होने वाली देरी को कम करेगी। इससे रेलगाड़ियों की समय की पाबंदी बेहतर होगी और उनका परिचालन सुव्यवस्थित हो जाएगा।

यह बाईपास महत्वपूर्ण दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर संपर्क को भी मजबूत करेगा और प्रमुख गलियारों पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करेगा। जंक्शन पर बिना किसी ठहराव या मार्ग संबंधी टकराव के रेलगाड़ियों की सीधी आवाजाही से परिचालन दक्षता और बढ़ेगी और यात्री तथा माल ढुलाई, दोनों तरह की सेवाओं की आवाजाही और भी सुगम हो जाएगी। इस परियोजना से आस-पास के कस्बों और जिलों के लिए भी संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि यह रेलगाड़ियों की समय-सारिणी को ज्यादा कुशल बनाने में सहायता करेगी और भीड़भाड़ के कारण होने वाली देरी को कम करेगी। कुल मिलाकर, ये रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल का उच्च क्षमता वाला और भविष्य के लिए तैयार रेल नेटवर्क बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। यह नेटवर्क आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, यात्रियों की सुविधा में सुधार करेगा है और तेलंगाना तथा पड़ोसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत बनाएगा।

रेल अवसंरचना परियोजनाओं से हनुमकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जिलों को फायदा होगा, इसके साथ ही पूरे तेलंगाना में कोयला, सीमेंट और कृषि माल की तेजी से आवाजाही में सहायता मिलेगी

जम्मू पहली बार पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से सीधे कश्मीर से जुड़ा

कश्मीर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी से हर मौसम में यहां तक पहुँच सुगम होगी, जिससे यात्रा अनुभव और भी सुखद होगा

सूत्र/रे.स.ब्यू - दशकों से जम्मू में ट्रेन पर सवार होकर सीधे श्रीनगर पहुँचने की कल्पना वास्तविकता से दूर केवल एक सपना ही थी। लेकिन अब वह सपना इतिहास बन गया है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने श्रीनगर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक विस्तार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे इतिहास में पहली बार जम्मू और कश्मीर सीधे ट्रेन सेवा से जुड़ गए हैं। अब एक सीधा और निर्बाध रेल कॉरिडोर इस क्षेत्र के दो सबसे प्रमुख केंद्रों को आपस में जोड़ता है, जो न केवल यात्रा को तेज बनाएगा बल्कि इस सुंदर क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और जन-संपर्क की तरवीर भी बदल देगा।

जम्मू तवी: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का मुख्य केंद्र बनकर उभरा

जम्मू तवी उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने वाले एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कन्याकुमारी, हावड़ा, मुंबई और अन्य बड़े शहरों जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए व्यापक रेल संपर्कों के साथ, यह स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों के बीच निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री वैष्णव ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया गया है। अब ट्रेन के जम्मू तवी तक पहुँचने से, देश भर के यात्रियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुगम हो जाएगी।

उच्च मांग एवं सुगम यात्रा अनुभव की ओर बढ़ते कदम

रेल मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वंदे भारत सेवा की शुरुआत के बाद से ही इसमें यात्रियों की फुल ऑक्युपेंसी देखी गई है, जो यात्रियों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूरे देश के लिए एक लाइफलाइन के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई है, जो इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यात्री क्षमता में एक बड़ी वृद्धि का प्रतीक है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विकास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष 6 जून को जम्मू-श्रीनगर रेल लिंक के उद्घाटन के एक वर्ष से भी कम समय के भीतर हुआ है, जिसने इस क्षेत्र में निर्बाध रेल संपर्क की आधारशिला रखी थी। विस्तारित वंदे भारत सेवा की शुरुआत इस ऐतिहासिक कॉरिडोर को और अधिक मजबूती प्रदान करती है, जो यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने, यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और जम्मू एवं श्रीनगर के बीच हर ऑल-वेदर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रेन को विशेष रूप से इस क्षेत्र की दुर्गम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम, जिसमें शून्य से नीचे का तापमान भी शामिल है, के अनुकूल डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसी विशेष प्रणालियाँ लगाई गई हैं जो अत्यधिक ठंड में भी ऑनबोर्ड उपकरणों की निर्बाध कार्यक्षमता सुनिश्चित करती हैं।

जम्मू और कश्मीर: धरती पर स्वर्ग

जम्मू और कश्मीर, जिसे अक्सर 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है, अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरी-भरी घाटियों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र अपने मिलनसार और जीवंत समुदायों का घर है, जिनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी विशिष्ट पहचान को और बढ़ाती है। बेहतर रेल संपर्क से पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे देश भर के अधिक लोग इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक जीवंतता का अनुभव कर सकेंगे।

जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस से क्षेत्र में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा



श्री वैष्णव ने कहा कि बेहतर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थानीय उत्पादों के सुगम परिवहन को सक्षम बनाकर आर्थिक विकास को भी गति दे रहा है। जम्मू-कश्मीर अपने प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, उत्कृष्ट पश्मीना शॉल, सेब और पारंपरिक हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए जाना जाता है, जिनकी पूरे भारत में भारी मांग है। बेहतर रेल संपर्क के साथ, देश भर के बाजारों में इन सामानों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक तेज और कुशल हो रही है, जिससे स्थानीय आजीविका को सहारा मिल रहा है और व्यापार के नए अवसरों का विस्तार हो रहा है।

व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को नई गति

श्री वैष्णव ने कहा कि इतनी अधिक ऊँचाई पर रेल परिचालन का भारत का यह पहला अनुभव है और इससे प्राप्त अनुभव भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे लाइन ने इस क्षेत्र में कार्गो की आवाजाही में काफी सुधार किया है, जिससे परिवहन लागत में कमी आई है और उर्वरक तथा दूध जैसे डेयरी उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए सुगम लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित हुई है। चेरी सहित अन्य कृषि उत्पादों को भी पार्सल सेवाओं के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों के लिए बाजार तक पहुँच आसान हुई है। उन्होंने आगे इस बात पर गौर किया कि रेल नेटवर्क ने लॉजिस्टिक्स को सरल बनाया है और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। भविष्य की ओर देखते हुए, अब हिमालयी क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव प्रणालियों को मजबूत करने और पुलों एवं सुरंगों के लिए उन्नत तकनीकों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कश्मीर घाटी: रेल कार्गो समन्वय और आर्थिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) के पूर्ण होने से कश्मीर घाटी अब भारतीय रेल नेटवर्क के शेष हिस्सों के साथ निर्बाध रूप से जुड़ गई है। इसने न केवल यात्रियों को लाभान्वित किया है, बल्कि क्षेत्र की व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति दी है। दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे पुल 'चिनाब रेल ब्रिज' और 'अजी खड्ड ब्रिज' जैसे इंजीनियरिंग के कीर्तिमानों के शुरु होने से इस क्षेत्र में हर मौसम में निरंतर रेल कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। इस परिवर्तनकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ने नियमित माल ढुलाई का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे आवागमन समय में काफी कमी आई है, विश्वसनीयता बढ़ी है और घाटी को राष्ट्रीय सप्लाय चैन के साथ और अधिक मजबूती से जोड़ा जा सका है। रेल मंत्री ने जम्मू से जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होकर कटरा तक की यात्रा की। ट्रेन में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि अब तक रेल नेटवर्क के माध्यम से श्रीनगर से देश के शेष हिस्सों में लगभग 2 करोड़ किलोग्राम सेब का परिवहन किया जा चुका है।

भविष्य की विस्तार योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण

श्री वैष्णव ने बताया कि जम्मू तवी स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, जिसमें बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए प्लेटफार्मों का विस्तार, अतिरिक्त प्रवेश द्वार और बेहतर यात्री सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य मार्गों पर रेल लाइनों के दोहरीकरण (लाइन डबलिंग) और क्षमता विस्तार सहित व्यापक बुनियादी ढांचागत पहलें, जम्मू-कश्मीर और देश के शेष हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करेंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि जालंधर-जम्मू सेक्शन के दोहरीकरण (डबलिंग) का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि दिल्ली-अंबाला सेक्शन को चार लाइनों में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसे हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि क्षमता बढ़ाने के लिए काजीगुंड और बारामूला के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। उन्होंने सूचित किया कि पुंछ-राजौरी रेल लिंक और उरी-बारामूला विस्तार जैसी परियोजनाएं वर्तमान में योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के चरणों में हैं। काजीगुंड-बारामूला लाइन को डबल करने से कश्मीर घाटी में माल ढुलाई और यात्री क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भीड़भाड़ कम होगी, यात्रा के समय में बचत होगी और वस्तुओं एवं पर्यटकों की सुगम आवाजाही संभव हो सकेगी। पुंछ-राजौरी रेल लिंक इतिहास में पहली बार, दो ऐसे जिलों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगा जहाँ पहले रेल सुविधाएं कम थी। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुँच में सुधार होगा। वहीं, उरी-बारामूला विस्तार रेल पट्टी को सीमा के ओर करीब ले जाएगा, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में पर्यटन और व्यापार के नए द्वार खुलेंगे और साथ ही नागरिकों के सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जून में उद्घाटन के बाद से, वंदे भारत की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है: रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव

अंबाला-जम्मू रेल मार्ग पर मल्टीट्रैकिंग का काम जारी है, वहीं क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पुंछ और राजौरी तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना है

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भौलि आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

1. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
2. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
3. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
4. रेलकर्म/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पंजिकृत कार्यालय

502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड,
नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003
से प्रकाशित।

कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिपोर्टर)
कार्यालय 8439 आर्य नगर
पहाड़गंज दिल्ली-55

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित
एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर,
कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह द्वारा दानापुर में 'सृजन' प्रेक्षागृह का किया गया उद्घाटन

सूत्र/रे.स.ब्यू - श्री छत्रसाल सिंह, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल द्वारा दिनांक 24.04.2026 को दानापुर स्थित सीनियर सेकेंडरी रेलवे स्कूल में, नवसृजित 'सृजन' प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता सिंह एवं संगठन की अन्य सदस्याएं भी उपस्थित थीं। यह प्रेक्षागृह वर्ल्ड क्लास लाइट और साउंड सुविधाओं वाला मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम हॉल के साथ दो सौ (200) दर्शकों के बैठने की क्षमता, LED वीडियो वॉल, कुशन वाली सीट के साथ पुशबैक सीटिंग चेयर आदि सुविधाओं से सुसज्जित है तथा पूर्णतः वातानुकूलित है। इसके स्टेज की चौड़ाई 34 फीट है, जो कि मोटर से संचालित होनेवाले पर्दों से सुसज्जित है। महाप्रबंधक महोदय द्वारा मधु विहार रेल कॉलोनी का निरीक्षण भी किया गया एवं कॉलोनीवासी रेलकर्मियों के परिवारों से वार्ता किये एवं आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही महाप्रबंधक द्वारा दानापुर रेलवे कॉलोनी में टाईप -5 श्रेणी के 5 यूनिट क्वार्टर के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया।



श्री छत्रसाल सिंह, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल द्वारा नवनिर्मित मंडल भंडार डिपो, दानापुर का उद्घाटन किया गया तथा डिपो के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री विनोद कुमार सहित मुख्यालय एवं मंडल के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

हरियाली के साथ सुरक्षित सफर: कैसे भारतीय रेल का वृक्षारोपण अभियान बदल रहा है रेल मार्ग

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे का वृक्षारोपण अभियान सभी जोन में लागू किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक समन्वित राष्ट्रव्यापी प्रयास को दर्शाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान लगाए गए कुल 81.59 लाख पौधों में से प्रमुख योगदान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (9.3 लाख), दक्षिण मध्य रेलवे (9 लाख), पूर्वोत्तर रेलवे (8.7 लाख) और उत्तरी रेलवे (8.5 लाख) का रहा है। रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसरों और उपलब्ध भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण से विभिन्न क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ रहा है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार लाने में सहायक है, जिससे यात्रियों के लिए रेल यात्रा अधिक हरित और स्वास्थ्यकर बन रही है।

यह व्यापक वृक्षारोपण प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हुए जलवायु लचीलापन को भी मजबूत करता है, साथ ही शोर और धूल को कम करने में मदद करता है। बेहतर हरित आवरण स्टेशनों और रेल मार्गों के आसपास सूक्ष्म जलवायु को संतुलित करता है, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव मिलता है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे पटरियों के किनारे वृक्षारोपण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधने में मदद करती हैं, जिससे कटाव कम होता है और विशेष रूप से पहाड़ी एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूस्खलन को रोका जा सकता है। वनस्पति आवरण सतह के बहाव को नियंत्रित करता है और जल अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पटरी के अस्थिर होने का जोखिम कम होता है। ये प्रकृति-आधारित उपाय न केवल रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय यात्रा भी सुनिश्चित करते हैं।

जल: संवयन, पुनर्चक्रण, ऑडिटिंग और पुनरुद्धार - जल संकट इस सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। प्रतिदिन लाखों लीटर पानी का उपयोग करने वाली भारतीय रेल- जो सैकड़ों वॉशिंग लाइनों, मेंटेंस डिपो, कैंटरिंग इकाइयों और यात्री सुविधाओं का संचालन करती है, ने अपने जल उपयोग को संतुलित करने के लिए ठोस और मापनीय कदम उठाए हैं। इसकी रणनीति व्यापक है: वर्षा जल का संग्रह, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, जल उपयोग का ऑडिट और रेलवे भूमि पर स्थित जल निकायों का पुनर्जीवन।

छत पर वर्षा जल संवयन (आरडब्ल्यूएच): जहां बारिश हो रही है वहीं उसका संचयन- 2016-17 से अब तक भारतीय रेल ने सभी जोनों में कुल 8,313 रूफट प रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं स्थापित की हैं। पिछले दो वर्षों में ही 2,915 नई संरचनाएं जोड़ी गईं, जिनमें 2024-25 में जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत 1,215 इकाइयां शामिल हैं। दक्षिण मध्य रेलवे इस पहल में अग्रणी है, जिसने 3,128 संरचनाएं स्थापित की हैं। ये संरचनाएं मानसून के दौरान वर्षा जल को संग्रहित कर एक ओर जलभराव रोकती हैं और दूसरी ओर भूजल स्तर को पुनर्भरित करती हैं। राजस्थान जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों या दक्कन के वर्षाछाया क्षेत्रों में ये प्रणालियां संचालन के लिए जीवनरेखा साबित हो रही हैं।

जल पुनर्चक्रण संयंत्र- भारतीय रेल ने सभी जोनों में कुल 185 जल पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किए हैं। 2015-16 से पहले जहां केवल 21 संयंत्र थे, वहीं पिछले वित्त वर्ष में ही 26 नए संयंत्र स्थापित किए गए। उत्तरी रेलवे 27 संयंत्रों के साथ अग्रणी है। ये संयंत्र कोच वॉशिंग और यार्ड संचालन से निकलने वाले जल को शुद्ध कर पुनः उपयोग योग्य बनाते हैं, जिससे ताजे जल की खपत कम होती है।

जल ऑडिट - 2015-16 से अब तक सभी रेलवे जोन में कुल 1,944 जल ऑडिट किए गए हैं, जिनमें से 2025-26 में अकेले 310 ऑडिट हुए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे 442 ऑडिट के साथ शीर्ष पर है। ये ऑडिट पानी की अत्यधिक खपत वाले क्षेत्रों, पाइपों के रिसाव और सिस्टम की खामियों की पहचान करते हैं, जिससे पानी की लक्षित बचत संभव होती है।

जल निकायों का पुनरुद्धार: प्रकृति को लौटाना- भारतीय रेलवे ने अपनी भूमि या उसके पास स्थित 109 जल निकायों (तालाब, टैंक और आर्द्रभूमि) का पुनरुद्धार किया है जो अतिक्रमण या उपेक्षा का शिकार थे। दक्षिण



मध्य रेलवे (34) और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (44) इसमें अग्रणी रहे हैं। ये पुनर्जीवित जल निकाय न केवल रेलवे बल्कि आसपास के समुदायों के लिए भी जल स्तर सुधारने और बाढ़/सूखे से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।

अहमदाबाद के कांकरिया में भारत का पहला जल-तटस्थ रेलवे डिपो- पश्चिम रेलवे के तहत अहमदाबाद का कांकरिया कोचिंग डिपो भारत की उन दुर्लभ औद्योगिक सुविधाओं में से एक बन गया है जो पूर्णतः 'वॉटर-न्यूट्रल' (जल-तटस्थ) है। यह डिपो कोच की धुलाई और रखरखाव के दौरान उत्पन्न लगभग सभी अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग करता है, जिससे बाहरी ताजे पानी के स्रोतों पर इसकी निर्भरता समाप्त हो गई है।

विद्युतीकरण मिशन: एक निर्णायक बदलाव- यदि कोई एक ऐसा बदलाव है जिसने भारतीय रेलवे के पर्यावरणीय स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया है, तो वह है ब्रॉड गेज नेटवर्क का आक्रामक विद्युतीकरण। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण कर दिया है। मार्च 2026 तक 69,873 रूट किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकृत हो चुके हैं, जो 2014 में मात्र 21,801 आरकेएम था। भारतीय रेलवे ने 2016-17 की तुलना में 2024-25 में 178 करोड़ लीटर डीजल बचाया है, जो कि 62% की बचत है। पश्चिम एशिया संकट के बीच इसने कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम किया है। डीजल से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली बिजली की ओर कदम बढ़ाना न केवल हरित विकल्प है, बल्कि वित्तीय रूप से भी जिम्मेदारी भरा निर्णय है।

बायो-टॉयलेट: रेल पर पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छता - भारतीय रेलवे ने बायो-टॉयलेट के माध्यम से यात्री स्वच्छता में बड़ा योगदान दिया है, 2014 से अब तक यात्री डिब्बों में 3.66 लाख से अधिक बायो-टॉयलेट लगाए गए हैं। इस पहल ने पटरियों पर मानव अपशिष्ट के सीधे विसर्जन को समाप्त कर दिया है। यह स्वदेशी तकनीक सूक्ष्मजीवों के उपयोग से अपशिष्ट को पानी और गैसों में बदल देती है, जिससे दुर्गंध और प्रदूषण कम होता है और रेलवे संपत्तियों का क्षरण भी रुकता है। यह पहल मिट्टी और ट्रैक के दूषित होने से रोककर, रेलवे की संपत्तियों में जंग लगने की समस्या को कम करके और पर्यावरण-अनुकूल कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीधे तौर पर किसी भी तरह के कचरे का निकास न होने देने और टिकाऊ स्वच्छता पद्धतियों का समर्थन करके, भारतीय रेलवे यात्रियों के आराम को बेहतर बना रहा है, साथ ही एक स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र और हरित भविष्य में भी अपना योगदान दे रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा : सूर्य और पवन से भविष्य को ऊर्जा- दिसंबर 2025 तक, रेलवे नेटवर्क में लगभग 909 मेगावाट के सौर संयंत्र और 103 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा, रेलवे ने राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के डेवलपर्स के साथ सौर, पवन और हाइब्रिड माध्यमों से 3,300 मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता के लिए समझौता किया है। यह कदम दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और मूल्य-स्थिर हरित बिजली की खरीद की ओर एक सोची-समझी पारी है।

एलईडी लाइटिंग: कुशलता से जगमगाता नेटवर्क- भारतीय रेलवे ने अपने सभी कार्यालयों, स्टेशनों और आवासीय कॉलोनिनों में 100% एलईडी लाइटिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे न केवल बिजली की खपत कम हुई है, बल्कि रोशनी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिससे यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल और प्लेटफॉर्म अधिक सुरक्षित और बेहतर हो गए हैं।

ऊर्जा संरक्षण: राष्ट्रीय पहचान- भारतीय रेलवे ने ऊर्जा दक्षता के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। व्यक्तिगत प्रयासों से आगे बढ़ते हुए रेलवे ने अपने पूरे सिस्टम में 'संरक्षण की संस्कृति' को आत्मसात कर लिया है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 में भारतीय रेलवे ने 3 अलग-अलग श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार अपने नाम किए हैं।

स्क्रेप से होने वाली लगातार आय और गैर-किराया राजस्व में वृद्धि से रेलवे को यात्री किराए में वृद्धि किए बिना स्टेशन अनुभव बेहतर बनाने में मदद मिली

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे, स्क्रेप से होने वाली निरंतर आय और गैर-किराया राजस्व स्रोतों में लगातार वृद्धि की मदद से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाते हुए अपनी वित्तीय स्थिरता को मजबूत कर रहा है और यह सभी सुविधाएं बिना यात्री टिकट किराए बढ़ाए मुमकिन हो पा रही हैं। निष्क्रिय संपत्तियों से मूल्य प्राप्त करके और किराए के अलावा अन्य नए राजस्व स्रोतों का विस्तार करके, रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि स्टेशन पर सुविधाओं, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार वित्तीय रूप से टिकाऊ तरीके से हासिल किए जाएं। यह संतुलित दृष्टिकोण कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, ग्राहक-केंद्रित निवेश और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर रणनीतिक फोकस को दर्शाता है, जो अधिक आरामदायक, आधुनिक और विश्वसनीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए रेलवे की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

भारतीय रेलवे ने स्क्रेप के मुद्रीकरण की अपार संभावनाओं को दर्शाया

भारतीय रेलवे ने स्क्रेप निपटान में एक अहम उपलब्धि हासिल की है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है। 6000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले, रेलवे ने 6813.86 करोड़ रुपए की स्क्रेप बिक्री दर्ज की, जो निर्धारित बेंचमार्क से कहीं अधिक है और उल्लेखनीय दक्षता दर्शाती है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है, जिसमें भारतीय रेलवे ने 5400 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 6641.78 करोड़ रुपए की स्क्रेप बिक्री की थी। निरंतर स्क्रेप मुद्रीकरण भारतीय रेलवे के कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन और पारदर्शी निपटान तंत्र के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस्तेमाल में ना आने वाली सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से हटाकर, संगठन न केवल निष्क्रिय परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त कर रहा है, बल्कि डिपो, यार्ड और कार्यशालाओं में महत्वपूर्ण स्थान भी खाली कर रहा है। यह पहल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर और अपशिष्ट संचय को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी अहम योगदान देती है।

रेलवे को सुदृढ़ और यात्री अनुभव को बेहतर बनाता गैर-किराया राजस्व

गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने का एक जरूरी स्तंभ बनकर उभरा है, जिससे पूरे नेटवर्क में यात्रियों को सीधा लाभ मिलता है। स्टेशन पुनर्निर्माण, विज्ञापन, रेलवे संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग और अन्य नवोन्मेषी पहलों जैसे माध्यमों से राजस्व उत्पन्न करके, एनएफआर यात्री किराए और माल ढुलाई से होने



वाली आय पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है। यह अतिरिक्त आय भारतीय रेलवे को आधुनिक बुनियादी ढांचे में पुनर्निवेश करने, स्टेशन सुविधाओं को उन्नत करने, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने, डिजिटल सेवाओं में सुधार करने और बेहतर ट्रेनें और सुरक्षा प्रणालियां शुरू करने में सक्षम बनाती है। कुल मिलाकर इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक और विश्वसनीय यात्रा अनुभव मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 290 करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 777.76 करोड़ रुपए तक एनएफआर आय में लगातार वृद्धि एक मजबूत विकास पथ को दर्शाती है, जो पांच वर्षों में लगभग 168% की कुल वृद्धि दर्ज करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित एनएफआर लक्ष्य 720.85 करोड़ रुपए था, जिसे वास्तविक आय 777.76 करोड़ रुपए तक पहुंचकर पहले ही पार कर लिया गया है, जो लगभग 107.9% की उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनएफआर आय 686.86 करोड़ रुपए थी। यह प्रक्रिया भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में रणनीतिक मुद्रीकरण पहलों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

प्रीमियम ब्रांड आउटलेट

एनएफआर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के स्वामित्व वाले सिंगल ब्रांड प्रीमियम आउटलेट स्थापित करने के लिए जोनल रेलवे को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे ने इस नीति के तहत कुछ नवोन्मेषी ब्रांडेड आउटलेट खोले हैं और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसी तर्ज पर अन्य ब्रांडेड स्टोर भी खोले जाएंगे। सभी भारतीय रेलवे में एनएफआर के जरिए 22 प्रीमियम ब्रांड आउटलेट किए गए हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) का उद्घाटन

रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों के परिसर में 50 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया और उसे लागू किया। पीएमबीजेके के स्टॉल भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। 12 मार्च 2024 को, सभी 50 पीएमबीजेके का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस पहल की सफलता को देखते हुए और कल्याणकारी योजना का और विस्तार करने के लिए, भारतीय रेलवे पर अतिरिक्त 100 पीएमबीजेके स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन अतिरिक्त 100 पीएमबीजेके में से 18 पीएमबीजेके का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 नवंबर 2024 को किया गया। अब तक, भारतीय रेलवे पर 150 में से 120 पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। भारतीय रेलवे पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) आउटलेट्स के और विस्तार का अधिकार जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को सौंप दिया गया है, ताकि पीएमबीजेके योजना के प्रसार में तेजी लाई जा सके, अधिक राजस्व उत्पन्न किया जा सके और साथ ही यात्रियों को इनका लाभ मिल सके।

क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की गई उल्लेखनीय पहल

रेलवे ने नवोन्मेषी विचारों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसके तहत की गई कुछ उल्लेखनीय पहलों में शामिल हैं: बहुस्तरीय कार पार्किंग, चिकित्सा देखभाल केंद्र, नर्सिंग पॉड, वैगन सफाई अनुबंध, सशुल्क सेवा के रूप में ई-व्हीलचेयर की सुविधा, स्वास्थ्य कियोस्क, गेमिंग जोन, प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन, प्लेटफॉर्म ब्रांडिंग, यात्री सुविधा और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खाली जगह का उपयोग आदि। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रीमियम को-वर्किंग स्पेस/डिजिटल लाउंज की एक नई पहल की है। इसमें हाई-स्पीड वाई-फाई, वर्कस्टेशन, चार्जिंग पॉइंट, कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं और आरामदायक बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है। अतिरिक्त सेवाओं में प्रिंटिंग, स्कैनिंग, जलपान और अन्य उपयोग संबंधी योजनाएं जैसे घंटे के हिसाब से वर्कस्पेस का उपयोग और बंडल पैकेज शामिल हैं। यह पहल रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक, आरामदायक और उत्पादक प्रतीक्षा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के बेहतर विचारों को अन्य रेलवे में भी लागू करने के लिए अन्य क्षेत्रीय रेलवे को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

यूडीआईडी कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, अब मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित दिव्यांग कोच में सफर संभव

रेल रियायती किराया सुविधा के पात्र या वैध आईडी धारक दिव्यांगजन एसएलआरडी और एलएसएलआरडी कोच में वैध यात्री के रूप में यात्रा कर सकते हैं

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोचों में यात्रा करने वाले अनाधिकृत यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि वास्तविक लाभार्थियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित हो सके



सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेल ने समावेशी यात्रा और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करते हुए, स्पष्ट किया है कि वैध 'यूनिक डिसेबिलिटी आईडी' (यूडीआईडी) कार्ड धारक दिव्यांगजनों को मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए चिह्नित अनारक्षित कोचों में यात्रा करने की अनुमति होगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी वैध यूडीआईडी कार्ड धारक दिव्यांगजन और भारतीय रेल द्वारा रियायती किराया सुविधा प्रदान किए गए दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के लिए चिह्नित 'सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन विद कम्पार्टमेंट फॉर दिव्यांगजन' (एसएलआरडी) या 'लगेज-कम-सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन विद कम्पार्टमेंट फॉर दिव्यांगजन' (एलएसएलआरडी) कोचों में यात्रा करने के लिए वैध यात्री माने जाएंगे बशर्ते उनके पास यात्रा करने का वैध अधिकार (टिकट) हो। रेलवे ने यह भी कहा है कि इन निर्धारित कोचों में यात्रा करते पाए गए अनाधिकृत यात्रियों पर रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लक्षित लाभार्थी बिना किसी

असुविधा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सभी रेल मंडलों को संबंधित अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है, ताकि इन प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'दिव्यांगजन कार्ड' (जिसे 'ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र' या ईपीआईसीएस के नाम से भी जाना जाता है) दिव्यांगजनों के लिए रेलवे पहचान पत्र है, जो उन्हें ट्रेन यात्रा पर रियायतें प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह कार्ड वैध दिव्यांगता/रियायत प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें कुछ श्रेणियों के लिए यूडीआईडी कार्ड भी स्वीकार्य है। कार्ड जारी करवाने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन भारतीय रेल के 'दिव्यांगजन पोर्टल' या केंद्र सरकार के 'सेवा पोर्टल' के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

सफर होगा और आसान: मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत में बढ़ेगी कोच संख्या, 20 कोच का स्थायी संचालन

इसके साथ, लगभग 23.45 प्रतिशत वंदे भारत रैक को 20 कोचों, 21 प्रतिशत को 16 कोचों और शेष को 8 कोचों में अपग्रेड किया गया है



सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे ने ट्रेन नंबर 22961/22962 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच से बढ़ाकर 20 कोच करने के विस्तार को स्थायी कर दिया है। यह बदलाव 28 अप्रैल, 2026 से शुरू हो गया है। बढ़ाए गए चार कोचों में तीन एसी चेंयर कार कोच और एक एग्जीक्यूटिव क्लास कोच शामिल हैं, जिससे यात्रियों को भारत के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा मांग वाले इंटर-सिटी रेल कॉरिडोर में से एक पर बैठने की बेहतर सुविधा मिलेगी। यह फैसला उस लगातार और जबरदस्त मांग का सीधा जवाब है जो इस सेवा के शुरू होने के बाद से देखी गई है। जो पहल शुरू में यात्रा की सबसे ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी बढ़ोतरी के तौर पर शुरू हुई थी, अब उसे एक स्थायी परिचालन व्यवस्था का रूप दे दिया गया है। यह भारतीय रेलवे की इस प्रतिबद्धता को दिखाता है कि वह अपनी क्षमता को, यात्रियों के उस भारोसे के हिसाब से बढ़ाएगी जो उन्होंने रेलवे पर दिखाया है। अब तक, 162 वंदे भारत सेवा शुरू की जा चुकी हैं, जिससे कई कॉरिडोर पर यात्रा का समय 45 प्रतिशत तक कम हो गया है। इनमें से, 90 सेवाएं 8-कोच वाली, 38 सेवाएं 20-कोच वाली और 34 सेवाएं 16-कोच वाली हैं। इससे पता चलता है कि लगभग 23.45 प्रतिशत वंदे भारत सेवा को 20 कोच वाली सेवा में अपग्रेड कर दिया गया है, जबकि लगभग 21 प्रतिशत सेवा 16 कोच वाली हैं और बाकी सर्विस 8-कोच वाली ही बनी हुई हैं। 491 किलोमीटर लंबा यह रूट पश्चिमी भारत के दो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्रिय शहरों को जोड़ता है, जो 5 घंटे 30 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करता है और बोरीवली, वापी, सूरत और वडोदरा में रुकता है। यह यात्रियों के एक विविध वर्ग की सेवा करता है, जिसमें कारोबारी यात्री, छात्र, रोजाना यात्रा करने वाले लोग और पर्यटक शामिल हैं। इनके लिए गति, आराम और विश्वसनीयता अब सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि उम्मीदें बन चुकी हैं। यह उम्मीद पूरी तरह से सही है। वित्त वर्ष 2025-26 में वंदे भारत सेवाओं से लगभग 4 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जिससे साल-दर-साल लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से,

वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 लाख से ज्यादा यात्राओं में 9.1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा दी है। पूरे नेटवर्क में यात्रियों की संख्या लगातार 100 प्रतिशत से ज्यादा रही है। ये आंकड़े न सिर्फ मांग को दर्शाते हैं, बल्कि यात्रा करने वाले लोगों के मन में इस सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के प्रति गहरे और बढ़ते भरोसे को भी दिखाते हैं। वंदे भारत ट्रेनों की बढ़ती लोकप्रियता कई ऐसे कारणों का मेल है, जो भारत के यात्रा करने के तरीके को बदल रहे हैं। रेल यात्रियों की एक नई पीढ़ी-जो ज्यादा युवा है, ज्यादा गतिशील है और जो अब आराम या समय की पाबंदी के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है-उसे वंदे भारत के रूप में एक ऐसी सेवा मिली है, जो उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है। यात्रा में लगने वाला कम समय, साफ-सुथरे कोच, ट्रेन के अंदर बेहतर अनुभव, और पारंपरिक सेवाओं की तुलना में समय की कहीं ज्यादा पाबंदी-इन सभी बातों ने इन ट्रेनों को एक के बाद एक, हर रूट पर यात्रियों की पहली पसंद बना दिया है। भारतीय रेलवे की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि नेटवर्क के सबसे ज्यादा मांग वाले कॉरिडोर पर मांग, क्षमता से लगातार आगे निकलती रही है। मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद सेवा का इस श्रेणी में स्थायी रूप से शामिल होना कोई अलग-थलग फैसला नहीं है, बल्कि यह एक बड़े, डेटा-आधारित प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रेलवे बदलते भारत की आकांक्षाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद सेवा के अलावा, 20901/20902 गांधीनगर कैपिटल-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक और अहम हाई-स्पीड लिंक मुहैया कराती है। गांधीनगर को मुंबई से जोड़ने वाला यह रूट, अहमदाबाद-गांधीनगर के बड़े क्षेत्र को भी सेवा देता है। यह व्यापार, प्रशासनिक और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए तेज और ज्यादा आरामदायक यात्रा का अनुभव देता है, साथ ही दोनों राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करता है।

ओडिशा में रेल बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार: ₹90,000 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर, नेटवर्क दामता और निष्पादन रफ्तार तेजी से हो रही है प्रगति: श्री अश्विनी वैष्णव



सूत्र/पी.आई.बी- भुवनेश्वर में भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई के भूमि पूजन समारोह के दौरान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में रेलवे बुनियादी ढांचे के तेजी से हो रहे कार्याकल्प पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य भर में कनेक्टिविटी और क्षमता वृद्धि पर सरकार के कड़े रुख को रेखांकित किया। श्री वैष्णव ने सूचित किया कि ओडिशा में वर्तमान में 90,000 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं, जो रेल नेटवर्क के अभूतपूर्व विस्तार का प्रतीक हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवेश का यह पैमाना राज्य में यात्री और माल ढुलाई दोनों बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओडिशा यात्रा के दौरान, श्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के चल रहे पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया और समय पर पूरा होने तथा उच्च गुणवत्ता वाले निष्पादन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्नत स्टेशन आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर यात्री आराम प्रदान करेगा, जो स्टेशनों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा केंद्रों में बदलने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रिकॉर्ड बजट आवंटन और स्टेशन पुनर्विकास अभियान

श्री वैष्णव ने बताया कि ओडिशा को 10,928 करोड़ का रिकॉर्ड रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले आवंटनों की तुलना में काफी अधिक है। इससे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 59 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्टेशनों को बेहतर सुविधाओं के साथ आधुनिक, यात्री-अनुकूल केंद्रों में बदलना है।

सभी जिलों में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार

कनेक्टिविटी के लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से ओडिशा के सभी 30 जिलों को रेल कनेक्टिविटी के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे समावेशी विकास सुनिश्चित होगा और दूरस्थ तथा आंतरिक क्षेत्रों का मुख्यधारा के रेल नेटवर्क के साथ बेहतर एकीकरण होगा।

तटीय और क्षेत्रीय संपर्कों को मजबूत करने वाली प्रमुख परियोजनाएं

मंत्री ने बालासोर से ब्रह्मपुर तक प्रस्तावित चार-लेन तटीय रेल कॉरिडोर जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों की ओर भी इशारा किया, जो तटीय बेल्ट की क्षमता को काफी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं से क्षेत्रीय गतिशीलता में सुधार होगा, भीड़भाड़ कम होगी और पूरे ओडिशा में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

विकास और कनेक्टिविटी की प्रेरक शक्ति बनती रेलवे

श्री वैष्णव ने कहा कि ये बदलावकारी रेलवे पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, आर्थिक विकास का समर्थन करेंगी और ओडिशा को राष्ट्रीय माल ढुलाई और यात्री नेटवर्क के साथ और अधिक निकटता से जोड़ेंगी। चल रहे निवेश और नीतिगत प्रोत्साहन ओडिशा को भारत के विस्तारित रेलवे बुनियादी ढांचे के प्रमुख लाभार्थी के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार हैं।

अहमदाबाद स्थित कंकरिया भारत का पहला वॉटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो बनाए इसने जल शुद्धिकरण के लिए पौधों का उपयोग करने की एक अद्भुत उपलब्धि अर्जित की

सूत्र/पी.आई.बी - पर्यावरण स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर न्यूट्रल रेलवे डिपो के रूप में उभरा है, जो दर्शाता है कि कैसे नवोन्मेषी कार्यप्रणालियां पारंपरिक रेलवे संचालन को पर्यावरण के अनुकूल मॉडल में बदल सकती हैं। यह पहल जल संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करती है, क्योंकि डिपो उन्नत उपचार और पुनः उपयोग प्रणालियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर पानी की बचत कर रहा है - जो 300 से अधिक घरेलू टैंकों के बराबर है। इस रूपांतरण का मूल आधार फाइटोरेमेडिएशन पर आधारित एक आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों का उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। डिपो ने कोच की धुलाई और रखरखाव जैसे नियमित कार्यकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार के लिए इस पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। जल को बहाए जाने के बजाय, इसे साफ करके पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे ताजे पानी के स्रोतों पर निर्भरता अत्यधिक कम हो जाती है। यह प्रणाली वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई बहु-चरणीय प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जिसमें प्रभावी शुद्धिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक और तकनीकी विधियों का संयोजन किया गया है। आर्द्रभूमि आधारित उपचार में, पौधे अशुद्धियों को अवशोषित करने और जल की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम चरण में, उपचारित जल को कार्बन और रेत निस्पंदन के साथ-साथ यूवी कीटाणुशोधन से गुजारा जाता है, जिससे यह परिचालन कार्यकलापों में पुनः उपयोग के लिए सुरक्षित हो जाता है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, बल्कि जल खपत की लागत को कम करके आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है। यह परियोजना पर्यावरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थिरता और अनुपालन साथ-साथ चलें। प्रतिदिन की बचत से लगभग 5.84 करोड़ लीटर पानी की वार्षिक बचत होती है, जिससे कांकरिया कोचिंग डिपो भारतीय रेलवे में कुशल जल प्रबंधन का एक आदर्श उदाहरण बन गया है। इस प्रकार की नवोन्मेषी और टिकाऊ कार्य प्रणालियों को अपनाकर, यह डिपो उदाहरण प्रस्तुत करता है कि प्रचालनगत दक्षता बनाए रखते हुए पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। कंकारिया कोचिंग डिपो को वॉटर न्यूट्रल सुविधा केन्द्र में परिवर्तित करना, रेलवे संचालन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जो सतत विकास और संसाधन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

मऊ और गाजीपुर को मिली नई रेल सेवा, दोहरीघाट-औड़िहार पैसेंजर ट्रेन शुरू

सूत्र/रे.स.ब्यू- केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोहरीघाट-औड़िहार पैसेंजर ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इस नई ट्रेन सेवा से मऊ और गाजीपुर जिलों के लोगों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती रेल यात्रा सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस सेवा को वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंदारा-दोहरीघाट मीटर गेज लाइन का निर्माण वर्ष 1904 में किया गया था, लेकिन इसका गेज परिवर्तन लंबे समय तक लंबित रहा। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस परियोजना को गति मिली और दिसंबर 2023 में नई लाइन पर रेल सेवा शुरू की गई। रेल मंत्री के अनुसार, उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। गंगा के दक्षिण में प्रयागराज, कानपुर, आगरा और दिल्ली को जोड़ने वाला चार लेन रेलवे कॉरिडोर विकसित किया गया है, जबकि गंगा के उत्तर में भी एक नया कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यह मार्ग गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा और गोरखपुर होते हुए दिल्ली से जुड़ेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 157 अमृत भारत स्टेशनों का विकास कार्य जारी है। कोविड महामारी के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 58 नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं और 568 ट्रेनों का विस्तार किया गया है। वर्तमान में राज्य में 40 अमृत भारत एक्सप्रेस और 32 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

उत्तरप्रदेश के लिए बुलेट ट्रेन

श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की है और इस पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कॉरिडोर पर प्रस्तावित यात्रा समय साझा किया: दिल्ली-आगरा: 58 मिनट, दिल्ली-लखनऊ: 2 घंटे 12 मिनट, दिल्ली-वाराणसी: 3 घंटे 33 मिनट, दिल्ली-अयोध्या: 2 घंटे 47 मिनट, लखनऊ-प्रयागराज: 48 मिनट, लखनऊ-वाराणसी: 1 घंटे 21 मिनट, लखनऊ-अयोध्या: 35 मिनट। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला प्रस्तावित बुलेट ट्रेन नेटवर्क, पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों से संपर्क मजबूत करेगा और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग और आम नागरिकों के लिए किफायती होगी और विकसित भारत की नींव रखेगी।

रेलवे बोर्ड की अतिरिक्त सदस्य/योजना/रेलवे बोर्ड सुश्री गीतिका पांडे ने किया डीएफसीसीआईएल स्टेशन का निरीक्षण



सूत्र/रे.स.ब्यू -रेलवे बोर्ड की अतिरिक्त सदस्य/योजना/रेलवे बोर्ड सुश्री गीतिका पांडे ने 11.05.2026 को न्यू श्रीमाधोपुर डीएफसीसीआईएल स्टेशन और मॉक-अप सेंटर का निरीक्षण किया और डीएफसीसीआईएल अधिकारियों के साथ बैठक की। सीजीएम/जयपुर श्री आर.एस. चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें डीएफसीसीआईएल में चल रही गतिविधियों और सर्वोत्तम रखरखाव प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने परिसंपत्ति रखरखाव, बुनियादी ढांचे के उचित रखरखाव और प्रभावी रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाने में डीएफसीसीआईएल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में 25000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। यह निरीक्षण और बातचीत सभी डीएफसीसीआईएल अधिकारियों के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक साबित हुई।

बरेका में महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने कर्मशाला तथा कंचनपुर एवं पश्चिमी उपनगर कॉलोनी का किया गहन निरीक्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू - बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में दिनांक 09 मई 2026 को महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने कर्मशाला तथा कंचनपुर एवं पश्चिमी उपनगर (दक्षिण) कॉलोनी का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे आवासों की वर्तमान स्थिति का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता एवं उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया।



तत्पश्चात महाप्रबंधक कर्मशाला पहुंचे जहां उन्होंने ओल्ड ब्लॉक शॉप का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री विवेक शील, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन एवं विपणन) श्री राम जन्म चौबे, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर-विद्युत श्री अनुराग कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक श्री सागर, उप मुख्य इंजीनियर श्री साकेत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, संयुक्त सचिव, कर्मचारी परिषद श्री प्रदीप कुमार यादव, अन्य सदस्य श्री अमित कुमार, श्री नवीन कुमार सिन्हा, श्री श्रीकांत यादव, श्री सुशील कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार यादव एवं श्री मनीष कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।

अपग्रेडेड यात्री आरक्षण प्रणाली (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) में अगस्त से रेलगाड़ियों की होगी शिफ्टिंग

40 साल पुरानी इस प्रणाली से अपग्रेडेड सिस्टम पर गाड़ियों की शिफ्टिंग के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए रेल मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे अगस्त से ट्रेनों को नई उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। नई दिल्ली स्थित रेल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी प्रणाली से नई तकनीक आधारित प्रणाली में बदलाव के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1986 में शुरू हुई इस प्रणाली में पिछले 40 साल में कई छोटे बदलाव किए गए। लेकिन अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इसके क्षमता का विस्तार किया गया है। रेल आरक्षण प्रणाली ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखे हैं। वर्ष 2002 में भारतीय रेलवे ने टिकटिंग में इंटरनेट का प्रयोग शुरू किया। आज यह प्रणाली इतनी लोकप्रिय है कि देश की ज्यादातर आबादी खिड़की की ओर रुख नहीं करती। देश में आज जितनी भी टिकटिंग की मांग है, उसका बड़ा हिस्सा (लगभग 88%) ऑनलाइन माध्यम से होता है। भारतीय रेल का मोबाइल ऐप रेलवन यात्रियों के बीच बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रेलवन ऐप की शुरुआत पिछले साल जुलाई में हुई थी। एक साल से कम समय में ही देशभर में अब तक 3.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। इस ऐप के लोकप्रिय होने के कई कारणों में से सबसे बड़ा कारण यह है कि यह ऐप देश के आम आदमी को रेल संबंधी सभी जानकारियाँ तो देता ही है, टिकटिंग तथा अन्य सेवाओं से जुड़ी उनकी शिकायतों का भी निपटारा करता है।

आज जब आप अपनी टिकट बनाते हैं, तो रेलवन ऐप आपको यह बताता है कि आपकी वेटिंग में दिख रही टिकट कन्फर्म होगी या नहीं। टिकट के कन्फर्म होने की सटीक संभावना भी अब आपको एआई के माध्यम से रेलवन ऐप बताते लगा है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रेलवन ऐप पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53 प्रतिशत से बढ़कर अब 94 प्रतिशत तक पहुँच गई है। रेलवन ऐप में इस तरह की कई एकीकृत एवं आधुनिक सुविधाएँ हैं, जो रेल संबंधी अन्य सभी सेवाओं को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। जैसे - आरक्षित, अनारक्षित तथा प्लेटफॉर्म आदि विभिन्न प्रकार



के टिकटों की बुकिंग, रद्दीकरण तथा रिफंड। इसके साथ-साथ आपके मौजूदा टिकट की वेटिंग स्थिति की ताजा जानकारी, ट्रेन के आने-जाने का समय, ट्रेन की वर्तमान स्थिति, ट्रेन के आने-जाने का प्लेटफॉर्म, आपके कोच की स्थिति, तथा रेल मदद जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी रेलवन ऐप पर उपलब्ध हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप रेलवन ऐप पर भोजन भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह ऐप आपको यह विकल्प देता है कि आपकी सीट तक आपका मनपसंद खाना पहुँच सके। आरामदायक एवं सेवापरक सुविधाओं से लैस यह रेलवन ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रोजाना इस ऐप के माध्यम से देशभर में 9.29 लाख टिकटें बुक हो रही हैं। इनमें 7.2 लाख टिकटें अनारक्षित तथा अन्य 2.09 लाख आरक्षित टिकटें हैं। अनारक्षित टिकटों में प्लेटफॉर्म टिकट भी शामिल है। एंज्रॉयड तथा आईओएस पर रेलवन ऐप को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जहाँ 3 करोड़ 16 लाख लोगों ने इसे गूगल प्ले स्टोर से अब तक डाउनलोड किया है, वहीं 33.17 लाख लोगों ने इसे ऐपल फोन में डाउनलोड किया है। देश में यात्रियों के लिए भारतीय रेल एक जीवन रेखा है। भारतीय रेल ने 2024-25 में यात्रियों के टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 43% की छूट के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत केवल 57 रुपये है।

भारतीय रेलवे ने विद्युत प्रणाली के उन्नयन और पुल आधारभूत ढांचे के लिए 895.30 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने रेलवे पुलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मेट्रो रेल की बिजली प्रणालियों में सुधार के लिए 895.30 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, संरचनात्मक सुरक्षा को मजबूत करना और शहरी रेल परिवहन प्रणालियों की विश्वसनीयता में सुधार करना है।

रेलवे के अनुसार, स्वीकृत योजनाओं के तहत पुलों के उन्नयन और मेट्रो रेल विद्युत प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे संचालन अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जा सकेगा।

कोलकाता मेट्रो विद्युत प्रणाली संवर्धन

मेट्रो रेल की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोलकाता मेट्रो रेलवे के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए 671.72 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- 291.06 करोड़ रुपये की लागत से 7 नए ट्रैक्शन सबस्टेशनों का निर्माण।
- कोलकाता मेट्रो रेलवे के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के लिए कईएसपी (एस्प्लेनेड मेट्रो) से केएमयूके (कवि सुभाष - न्यू गरिया) तक सहायक सबस्टेशन (एसएस) और ट्रैक्शन सबस्टेशन (टीएसएस) प्रणालियों का संवर्धन और उन्नयन के साथ केएनटीजे (नेताजी मेट्रो स्टेशन) से केकेवीएस (कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन) तक एलिवेटेड सेक्शन में बिजली आपूर्ति का संवर्धन शामिल है। इसमें मौजूदा 11 केवी प्रणाली को 33 केवी प्रणाली में अपग्रेड करना शामिल है, जिसकी लागत 380.66 करोड़ रुपये है।

1980 के दशक में निर्मित कोलकाता मेट्रो प्रणाली को मूल रूप से लगभग 5 मिनट के अंतराल पर ट्रेन संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। यात्रियों की बढ़ती मांग के साथ अधिक आवृत्ति पर संचालन की आवश्यकता बढ़ गई है। इस परियोजना की मंजूरी के साथ कोलकाता मेट्रो 2.5 मिनट के अंतराल पर चलने में सक्षम होगी जिससे लाइन की क्षमता और सेवा आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मौजूदा सबस्टेशन और उपकरण अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच



रहे हैं और स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता के कारण रखरखाव संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्वीकृत उन्नयन से विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ेगी और समग्र यात्री सेवा में सुधार होगा।

आद्रा डिवीजन में पुल अवसंरचना को मजबूत करना

दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत एमडीकेडी-डीएमए (मधुकुंडा-दामोदर) खंड के बीच पुल संख्या 520 यूपी और 520 डीएन (आधार संरचना) के निर्माण के साथ-साथ संबंधित यार्ड पुनर्निर्माण और पुल के पहुंच मार्गों में ट्रैक कार्यों के लिए 223.58 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है।

मौजूदा दामोदर पुल (पुल संख्या 520), जिसका निर्माण क्रमशः 1965 (यूपी लाइन) और 1903 (डीएन लाइन) में हुआ था, काफी पुराना हो चुका है और संरचनात्मक रूप से कमजोर होने के संकेत दिखाता है जिसके कारण नींव और आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

यह खंड आसनसोल और टाटानगर के बीच एक महत्वपूर्ण रेलवे लिंक है जो एक महत्वपूर्ण डीएफसी फीडर मार्ग और कोयला गलियारे (सिनी-पुरुलिया-आसनसोल) का हिस्सा है और इस पर 67 जीएमटी का उच्च यातायात घनत्व है। यह परियोजना सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन दक्षता में सुधार लाएगी।

इस पुनर्विकास से रेल संपर्क में सुधार होने के कारण दुर्गापुर-आसनसोल क्षेत्र में स्थित प्रमुख उद्योगों जिनमें आईआईएससीओ संयंत्र, एसीसी संयंत्र और ताप विद्युत इकाइयां शामिल हैं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आधुनिक, सुरक्षित और उच्च क्षमता वाली रेल प्रणालियों की ओर

ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, सुरक्षा संवर्धन और क्षमता विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। पुल परियोजना से महत्वपूर्ण माल ढुलाई और औद्योगिक संपर्क मजबूत होगा, वहीं मेट्रो विद्युत उन्नयन से कोलकाता में उड़ानों की आवृत्ति बढ़ेगी, विश्वसनीयता में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

भारतीय रेलवे बढ़ती परिवहन मांगों को पूरा करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश करना जारी रखे हुए है। इसके साथ ही सुरक्षित, कुशल और भविष्य के लिए तैयार रेल संचालन सुनिश्चित कर रहा है।

आवश्यक सूचना

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियों के संचालन एवं अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

गाड़ी संख्या 02417/02418 प्रयागराज जंक्शन-दादरी-प्रयागराज जंक्शन ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी	
02417 प्रयागराज जंक्शन-दादरी	02418 दादरी-प्रयागराज जंक्शन

आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
----	20:00	प्रयागराज जंक्शन	09:00	----
20:50	20:52	सिराथू	07:05	07:07
21:48	21:50	फतेहपुर	06:00	06:02
23:00	23:05	गोविन्दपुरी	05:05	05:10
00:25	00:27	फर्रूद	03:05	03:07
02:33	02:35	इटावा जं.	02:25	02:27
03:10	03:12	शिकोहाबाद जंक्शन	01:38	01:40
04:05	04:10	टुण्डला जंक्शन	00:28	00:33
04:48	04:50	हाथरस जंक्शन	23:45	23:47
05:13	05:15	अलीगढ़ जंक्शन	23:20	23:22
05:53	05:55	खुर्जा जंक्शन	22:48	22:50
07:15	----	दादरी	----	22:15

• प्रयागराज जंक्शन से - गाड़ी संख्या 02417 दिनांक 11.05.2026 से 31.07.2026 • दादरी से - गाड़ी संख्या 02418 दिनांक 11.05.2026 से 01.08.2026 • गाड़ी संरचना - सामान्य श्रेणी-05, स्लीपर श्रेणी-08, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी - 01, वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी - 01

गाड़ी संख्या 04123/04124 प्रयागराज जं.-हज़रत निज़ामुद्दीन विशेष रेलगाड़ी

आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
----	15:25	प्रयागराज जंक्शन	09:10	----
16:11	16:13	शंकरगढ़	07:35	07:37
16:37	16:39	डभौरा	07:05	07:07
17:25	17:30	मानिकपुर जंक्शन	06:30	06:35
18:00	18:02	चित्रकूट धाम कर्वी	04:38	04:40
18:45	18:47	अतर्रा	04:10	04:12
19:25	19:30	बाँदा	03:40	03:45
20:23	20:25	महोबा जंक्शन	02:40	02:42
20:42	20:44	कुलपहाड़	02:00	02:02
22:02	22:04	हरपालपुर	01:35	01:37
22:24	22:26	मऊरानीपुर	01:15	01:17
00:50	00:55	वीरांगना लक्ष्मीबाई	00:05	00:10
02:20	02:25	ग्वालियर	22:15	22:20
04:20	04:22	धौलपुर जंक्शन	20:23	20:25
06:20	06:25	आगरा छावनी	19:05	19:10
07:50	07:55	मथुरा जंक्शन	18:05	18:10
08:50	08:52	कोसी कलाँ	17:18	17:20
11:35	-----	हज़रत निज़ामुद्दीन	----	15:45

• प्रयागराज जंक्शन से - गाड़ी संख्या 04123 (प्रत्येक बुधवार व रविवार) दिनांक : 13.05.2026 से 28.06.2026 • हज़रत निज़ामुद्दीन से - गाड़ी संख्या 04124 (प्रत्येक गुरुवार व सोमवार) दिनांक : 14.05.2026 से 29.06.2026 • गाड़ी संरचना : स्लीपर श्रेणी - 08, सामान्य श्रेणी - 09, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी - 01, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी - 01

विशेष रेलगाड़ियों के संचालन अवधि में विस्तार

गाड़ी सं०	स्टेशन से- स्टेशन तक	संचालन का दिन	विस्तारित तिथि
05045	लालकुआँ जंक्शन-राजकोट जंक्शन	रविवार	17.05.26 से 12.07.26
05046	राजकोट जंक्शन-लालकुआँ जंक्शन	सोमवार	18.05.26 से 13.07.26
04823	जोधपुर-मऊ जंक्शन	रविवार	24.05.26 से 12.07.26
04824	मऊ जंक्शन-जोधपुर	मंगलवार	26.05.26 से 14.07.26
01053	देवलाली-दानापुर	शनिवार	09.05.26 से अगले आदेश तक
01054	दानापुर-देवलाली	सोमवार	11.05.26 से अगले आदेश तक
04127	*कानपुर सेन्ट्रल-गुवाहाटी	गुरुवार	07.05.26 से 14.05.26
04128	*गुवाहाटी-कानपुर सेन्ट्रल	शुक्रवार	08.05.26 से 15.05.26
06597	*यशवंतपुर जं.-योग नगरी ऋषिकेश	गुरुवार	07.05.26 से 09.07.26
06598	योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर जं.	शनिवार	09.05.26 से 11.07.26

नोट : * उपरोक्त गाड़ी संख्या 04127/04128 कानपुर सेन्ट्रल-गुवाहाटी विशेष रेलगाड़ी संशोधित गाड़ी संरचना सामान्य श्रेणी-06, स्लीपर-08, वातानुकूलित तृतीय-02 के साथ चलेगी।

* उपरोक्त गाड़ी संख्या 06597 यशवंतपुर जं.-योग नगरी ऋषिकेश विशेष रेलगाड़ी का योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर आगमन 10:20 के स्थान पर 10:15 पर होगा।

नोट : ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन न० 139 या Railmadad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

**उत्तर मध्य रेलवे**North central railwayswww.ncr.indianrailways.gov.in**1057/26 (C)**

महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे का दौरा : झाँसी परिक्षेत्र एवं वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन का व्यापक निरीक्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू - दिनांक 13.05.2026 को महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे श्री नरेश पाल सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिरुद्ध कुमार की उपस्थिति में वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन, झाँसी यार्ड एवं मंडल के विभिन्न महत्वपूर्ण रेल परिसरों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, परिचालन व्यवस्थाओं एवं भविष्य की विकास योजनाओं का गहन अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

महाप्रबंधक ने सर्वप्रथम झाँसी यार्ड का निरीक्षण किया तथा सीपरी पुल के समीप प्रस्तावित नई वाशिंग पिट साइट का अवलोकन कर भविष्य की विकास योजनाओं एवं आधारभूत संरचना विस्तार कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा रखरखाव सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया।

इसके उपरांत उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन का औचक निरीक्षण करते हुए प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय एवं शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने हेतु सभी व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखने पर बल दिया।

तदोपरांत महाप्रबंधक ने मंडलीय रेलवे चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड, आईसीयू, औषधि भंडार एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का अवलोकन करते हुए मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने पर बल देते हुए शल्य चिकित्सा कक्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किए जाने के निर्देश प्रदान किए।

निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत महाप्रबंधक ने प्रस्तावित होलिडे होम एवं होटलिंग एरिया के साइट प्लान का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एसी लोको शेड का निरीक्षण करते हुए आधारभूत



संरचना कार्यों में तेजी लाने, रखरखाव व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा अनुपयोगी (कंडम) लोको को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए।

वैगन मरम्मत कारखाना के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हेरिटेज म्यूजियम का अवलोकन कर इसे आम नागरिकों के लिए खोले जाने के निर्देश भी प्रदान किए।

महाप्रबंधक महोदय श्री नरेश पाल सिंह द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में स्थित नवीन कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संचालन व्यवस्थाओं, मॉनिटरिंग सिस्टम एवं उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आधुनिक तकनीक आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया।

इसके पश्चात महाप्रबंधक ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में बैठक कर मंडल में संचालित विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्री सुविधाओं,

स्वच्छता, सुरक्षा, संरक्षा तथा परिचालन दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया तथा रेल परिसरों में निरंतर सुधार एवं आधुनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया।

उन्होंने मंडल कार्यालय में सभी यूनियन और एसोसिएशन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कर्मचारी कल्याण, कार्य परिस्थितियों एवं संगठनात्मक समन्वय से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक महोदय द्वारा एसी लोको शेड को 1 लाख रुपए, वैगन मरम्मत कारखाना को 50 हजार रुपए एवं कंट्रोल रूम को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन धनराशि की घोषणा की गई।

नैनी-मानिकपुर रूट के शंकरगढ़-मझियारी - बरगढ़

रेल खंड पर ‘ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग’ का सफल शुभारंभ

उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं श्री सतेंद्र कुमार प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर, श्री ए. के. राय मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर/प्रोजेक्ट/समन्वय तथा श्री भोलेंद्र सिंह मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर/प्रोजेक्ट, प्रयागराज के नेतृत्व में, नैनी-मानिकपुर रूट पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है।

दिनांक 12/05/2026 शंकरगढ़ - मझियारी और मझियारी - बरगढ़ रेल खंडों के बीच 16.2 किलोमीटर की दूरी में ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया।

यह कार्य पूर्व-नियोजित ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान संपन्न किया गया और कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ट्रेन सेवाओं को निर्धारित समय पर बहाल कर दिया गया।

इस आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली की शुरुआत से अब एक ही दिशा में पर्याप्त अंतर रखते हुए एक के बाद एक कई ट्रेनें सुरक्षित रूप से चलाई जा सकेंगी। इससे इस व्यस्त रेल खंड की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी



महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह द्वारा गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन के डाउन लाइन में बीओबीआर रेक का फुटप्लेट निरीक्षण किया गया

सूत्र/रे.स.ब्यू - महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह ने प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक श्रीमती इंदू रानी दुबे के साथ दिनांक 07.05.2026 को गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन में बीओबीआर रेक का फुटप्लेट निरीक्षण किया। ग्रैंड कॉर्ड (जीसी) लाइन की शुरुआत लॉर्ड मिंटो ने 1906-07 में किया था जिसका एक भाग धनबाद मंडल का गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन है। यह रेलखंड चुनौतीपूर्ण है जिसमें 1:80 का रूलिंग ग्रेडिएंट, तीन सुरंग, छोटी पहाड़ियाँ और ऊँचे टीले हैं। आजादी के पूर्व बने इस रेलखंड में टनल की उंचाई सीमित होने और अवरोध के कारण बीओबीआर वैगन का परिचालन पहले नहीं किया जाता रहा है। परंतु पूर्व मध्य रेल ने आई.आई.टी.-आई.एस.एम. धनबाद के साथ मिलकर टनल रीडिजाइन और डाइमेंशन बढ़ाने जैसी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया और इसके फलस्वरूप डाउन लाइन में खाली बीओबीआर का परिचालन ट्रायल संभव हो सका है।

इससे चुनौतीपूर्ण गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन में बीओबीआर रेक ऑपरेशन शुरू करने तथा बाढ़, बरौनी और सलाकाटी (नॉर्थईस्ट) एन.टी.पी.सी प्लांट्स के लिए वैगन टर्नराउंड में सुधार होगा। विदित हो कि इसके पहले गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन के रास्ते बाढ़, बरौनी एन.टी.पी.सी प्लांट्स हेतु कोयले का परिवहन बॉक्स-एन रेक द्वारा ही किया जाता है। अभी बीओबीआर रेक में धनबाद मंडल में कोयला लोडिंग के उपरांत इसे प्रधानखांटा- आसनसोल-झाझा के रास्ते बाढ़, बरौनी और सलाकाटी (नॉर्थईस्ट) एन.टी.पी.सी प्लांट्स हेतु कोयले का परिवहन किया जाता है। इसमें जीसी लाइन के तुलना में ज्यादा समय लगता है। वापसी में भी इसी रूट से खाली बीओबीआर रेक धनबाद मंडल को मिलता है। परंतु अब जीसी लाइन के गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन द्वारा बीओबीआर रेक की वापसी धनबाद मंडल को हो सकेगी। इससे वैगन टर्न राउंड में काफी कमी आएगी और रेक की उपलब्धता बढ़ जाने से ज्यादा लोडिंग संभव हो पाएगा।

रेल की हर अपडेट अब आपके मोबाइल पर

बस स्कैन करें यह कोड

रेल समाचार ब्यूरो
की वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए अभी स्कैन करें

भारत न्यूजीलैंड एफटीए से आयुष को मिला वैश्विक मंच, आरोग्य कर्मियों के लिए खुले नए द्वार



सूत्र/रे.स.ब्यू- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहुंच के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह समझौता आयुष प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एक नए फ्रेमवर्क के केंद्र में रखता है। यह भविष्योन्मुखी समझौता न केवल भारत के व्यापार के दायरे को विस्तार देता है, बल्कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए वैश्विक मान्यता, गतिशीलता और संस्थागत सहयोग के अभूतपूर्व अवसर भी खोलता है। इस ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक रूप से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और ज्ञान-आधारित साझेदारियों को और गहरा करने के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पहली बार, न्यूजीलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत एक

समर्पित स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं में व्यापार के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। यह ऐतिहासिक प्रावधान भारत की समृद्ध आरोग्य विरासत को औपचारिक रूप से मान्यता देता है और आयुष के साथ-साथ न्यूजीलैंड की जनजाति 'माओरी' की स्वास्थ्य पद्धतियों को, समकालीन और विश्व स्तर पर प्रासंगिक स्वास्थ्य समाधान के रूप में स्थापित करता है।

आयुष सेवाओं के लिए वैश्विक मान्यता और नए बाजार

यह समझौता सेवा क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में बाजार तक पहुँच को सुगम बनाता है, जिससे भारतीय आयुष चिकित्सकों, आरोग्य संस्थानों और आयुष सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूजीलैंड के बाजार के साथ जुड़ने के नए अवसर पैदा होंगे। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा,

सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी में सहयोग को बढ़ावा देकर, यह मुक्त व्यापार समझौता निवारक, संवर्धक और एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल मॉडलों में भारत के नेतृत्व को और मजबूती प्रदान करेगा।

इस फ्रेमवर्क से चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलने, संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने, अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करने और भारत के 'आरोग्य तंत्र' के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को सहायता मिलने की उम्मीद है।

आयुष और आरोग्य कर्मियों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते

इस समझौते के परिणामस्वरूप कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए आगे बढ़ने के नियोजित मार्ग खुलेंगे। एक विशेष वीजा कोटा के माध्यम से आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों और अन्य भारतीय सांस्कृतिक एवं ज्ञान क्षेत्र के पेशेवरों को लंबी अवधि के लिए न्यूजीलैंड में काम करने की सुविधा मिलेगी। यह प्रावधान कुशल आरोग्य पेशेवरों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत के उभरते स्वरूप को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है।

पारंपरिक ज्ञान और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना

यह एफटीए आयुष और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में तकनीकी सहयोग को भी संस्थागत रूप देता है और शिक्षा, प्रशिक्षण, मानकों के विकास और आरोग्य सेवाओं के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखता है। पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक व्यापार ढांचे में एकीकृत करके, यह समझौता सतत स्वास्थ्य पद्धतियों और जन-केंद्रित विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता आयुष को राष्ट्रीय विरासत से वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की मुख्यधारा में ले जाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह समझौता अंतरराष्ट्रीय बाजारों को खोलकर, पेशेवरों को सक्षम बनाता है और अंतर-सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर, आयुष को वैश्विक कल्याण और समग्र स्वास्थ्य के एक स्तंभ के रूप में स्थापित करने के भारत के दृष्टिकोण को सशक्त बनाता है।

एआईआईए-आईसीएआईएनई ने एमएसएमई हैकाथन 5.0 में अपने अभूतपूर्व विचार के चयन के साथ उत्कृष्टता कायम की



सूत्र/पी.आई.बी- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने अपने इनक्यूबेशन सेंटर आईसीएआईएनई के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करते हुए एमएसएमई आइडिया हैकाथन 5.0 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आयुर्वेद क्षेत्र को समर्पित एकमात्र प्रमुख मेजबान संस्थान के रूप में एआईआईए ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रभावशाली नवाचारों की पहचान, पोषण और विस्तार करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है।

एआईआईए के निदेशक पी.के. प्रजापति ने कहा, "एमएसएमई आइडिया हैकाथन 5.0 में यह उपलब्धि आयुर्वेद इकोसिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति एआईआईए की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईसीएआईएनई के माध्यम से हम न केवल नए विचारों का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली और विस्तार योग्य समाधानों में परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत मंच भी तैयार कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक स्वास्थ्य उन्नति में योगदान दें।" उन्होंने कहा कि 'एमआईटीई ओयूटी' के चयन से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार को जोड़ने की हमारी कल्पना और मजबूत होती है, जिससे वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

एमएसएमई आइडिया हैकाथन 5.0, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक पहल है, छात्रों, नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स के बीच नवाचार, उद्यमिता और समस्या-समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उच्च-क्षमता वाले विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। चयनित नवाचारों को 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के साथ-साथ देशभर के मान्यता प्राप्त होस्ट संस्थानों के माध्यम से संरचित मेंटरशिप और इनक्यूबेशन सहायता भी प्रदान की जाती है।

इस हैकाथन न की शुरुआत से ही नामित मेजबान संस्थानों में से एक के रूप में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विशेष रूप से आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने इनक्यूबेशन इकोसिस्ट में आईसीएआईएनई के माध्यम से, संस्थान तकनीकी मार्गदर्शन, वैलिडेशन, अवसंरचना तक पहुंच और रणनीतिक सहयोग सहित समग्र सहायता प्रदान करता है, जिससे नवाचारपूर्ण विचारों को विस्तार योग्य और टिकाऊ उद्यमों में परिवर्तित किया जा सके।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आईसीएआईएनई के प्रभारी शिवकुमार हर्थी ने कहा, "आईसीएआईएनई में हमारा ध्यान ऐसे विचारों को प्रोत्साहित करने पर है, जिनमें सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता हो। 'एमआईटीई ओयूटी' का चयन हमारे इनक्यूबेशन इकोसिस्टम की मजबूती और नवोन्मेषकों को उनके हर चरण में समर्थन देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा उद्देश्य स्टार्टअप्स को उचित मेंटरशिप, अवसंरचना और रणनीतिक दिशा प्रदान कर नवाचारी अवधारणाओं को सफल उद्यमों में बदलने में सक्षम बनाना है।"

आयुष मंत्रालय के अंतराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों में तेजी



उच्च स्तरीय कोर समिति की बैठक में योग दिवस के प्रभावी आयोजन के लिए सुपरेखा तैयार की गई

सूत्र/पी.आई.बी- अंतराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 के भव्य और प्रभावशाली आयोजन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आयुष मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कोर कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने की और इसमें भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस बैठक में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले, खेल मंत्रालय और डाक मंत्रालय जैसे विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, आयुष मंत्रालय के सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2026 का आयोजन, पिछले वर्षों में रखी गई मजबूत नींव पर आधारित होगा और साथ ही जन-भागीदारी और अंतराष्ट्रीय सहयोग के नए आयाम भी प्रस्तुत करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी मंत्रालयों और हितधारकों के समन्वित प्रयासों से स्वास्थ्य, सद्भाव और सामूहिक कल्याण के एक शक्तिशाली साधन के रूप में योग की वैश्विक प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, यह बैठक संस्थागत समन्वय, प्रारंभिक समीक्षा और समन्वित कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। बैठक का संचालन आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा डैश ने किया। आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री अलारमेलमंगई डी. और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान अंतराष्ट्रीय योग दिवस पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें इसके वैश्विक विकास, विस्तार और प्रभाव को रेखांकित किया गया। चर्चा का मुख्य विषय 2026 के अंतराष्ट्रीय योग दिवस के विस्तार, पहुंच और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। समन्वित प्रचार रणनीतियों, सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने और समाज के विभिन्न वर्गों के दैनिक जीवन में योग को एकीकृत करने के उद्देश्य से अभिनव पहलों पर जोर दिया गया। मंत्रालयों को योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ अपने-अपने कार्यक्रमों को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

आयुष मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले संस्करणों की अभूतपूर्व सफलता, जिसमें 2025 की व्यापक पहुंच भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्ष 2026 के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपना रही है। संरचित उलटी गिनती अभियान, डिजिटल सहभागिता रणनीतियाँ और समावेशिता, स्थिरता और युवा भागीदारी पर केंद्रित विषय-गत कार्यक्रम जैसे तैयारी संबंधी प्रयास सक्रिय रूप से किए जा रहे हैं।

बैठक में प्रतिष्ठित स्थानों पर योग प्रदर्शनों के आयोजन, वैश्विक स्तर पर पहुंच बढ़ाने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थागत भागीदारी को मजबूत करने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक का समापन सभी भाग लेने वाले मंत्रालयों और विभागों के बीच इस साझा संकल्प के साथ हुआ कि वे घनिष्ठ समन्वय में काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 12वां अंतराष्ट्रीय योग दिवस भारत और विश्व भर में अभूतपूर्व पैमाने, दृश्यता और प्रभाव के साथ मनाया जाए।



जून-जुलाई में निकलिये आध्यात्मिक सफर पर, आईआरसीटीसी शुरू करेगा विशेष धार्मिक ट्रेन



सूत्र/आई.आर.सी.टी.सी- इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो विशेष यात्रा पैकेजों की घोषणा की है। यह सेवाएं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से संचालित की जाएंगी, जिनमें यात्रियों को देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों एवं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। पहले पैकेज के अंतर्गत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, आंमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, भेंट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तथा घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। यह यात्रा 12 जून 2026 से 23 जून 2026 तक 11 रात और 12 दिन की होगी।



इस यात्रा के लिए यात्रियों के चढ़ने और उतरने के स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई तथा ललितपुर जंक्शन निर्धारित किए गए हैं। पैकेज शुल्क इकोनॉमी श्रेणी (स्लीपर क्लास) के लिए 24,100 रुपये प्रति व्यक्ति, स्टैंडर्ड श्रेणी (3 एसी) के लिए 40,890 रुपये प्रति व्यक्ति तथा कम्फर्ट श्रेणी (2 एसी) के लिए 54,390 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। आईआरसीटीसी द्वारा दूसरी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन दक्षिण भारत धार्मिक यात्रा के लिए संचालित की जा रही है। इस यात्रा में तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, कन्याकुमारी स्थानीय दर्शन तथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मरकापुर के दर्शन कराए जाएंगे। यह यात्रा 29 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक 11 रात और 12 दिन की होगी। दक्षिण भारत यात्रा के लिए ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, एमबीडीपी प्रतापगढ़, प्रयागराज और मानिकपुर स्टेशनों से यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। पैकेज में 2 एसी, 3 एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का शाकाहारी भोजन तथा एसी और नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण शामिल रहेगा। इस यात्रा के लिए इकोनॉमी श्रेणी का किराया 24,350



भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से 7 ज्योतिर्लिंग एवं दक्षिण भारत यात्रा करने का सुनहरा मौका

रुपये, स्टैंडर्ड श्रेणी का किराया 41,800 रुपये तथा कम्फर्ट श्रेणी का किराया 55,750 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। यात्रियों को एलटीसी और ईएमआई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आईआरसीटीसी ने इसके अतिरिक्त कई हवाई यात्रा और रेल टूर पैकेज भी शुरू किए हैं। विदेशी यात्रा पैकेजों में भूटान, सिंगापुर-मलेशिया, नेपाल, बाली, वियतनाम और श्रीलंका शामिल हैं। वहीं घरेलू यात्रा पैकेजों में अरुणाचल प्रदेश तवांग, धर्मशाला-खज्जियार, कश्मीर, दार्जिलिंग, 4 शक्तिपीठ यात्रा, 03 ज्योतिर्लिंग यात्रा, हम्पी, भोपाल-पंचमणी, लद्दाख, दिव्या दक्षिण, हैदराबाद मल्लिकार्जुन, उज्जैन महाकाल, केरला, अंडमान, मैसूर-ऊटी, गुजरात और राजस्थान यात्रा पैकेज शामिल किए गए हैं। रेल टूर पैकेजों में मां वैष्णो देवी, शिरडी-शनि सिंगणापुर-त्रियंबकेश्वर, अहमदाबाद-स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नैनीताल, रामेश्वरम-मदुरै तथा चंडीगढ़-शिमला-कुफरी यात्रा प्रमुख हैं। आईआरसीटीसी के अनुसार इन पैकेजों की बुकिंग “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी। यात्री पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय तथा IRCTC Tourism के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।



अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए 9236391908, 8287930908, 8287930199, 9717649141, 7302821864, 9415042930, 9305111764, 8287930913 और 8595924294 मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

जम्मू मंडल के परिचालन वाणिज्यिक, पर्सनल और सामान्य प्रशासन विभागों में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

सूत्र/रे.स.ब्यू - साल 2025 में जम्मू मंडल बनने के बाद रेल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने व मंडल के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए साथ ही कार्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे के महत्वपूर्ण विभाग जिसमें ऑपरेटिंग (परिचालन), कमर्शियल (वाणिज्यिक), पर्सनल (कार्मिक) और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (सामान्य प्रशासन) विभागों के विभिन्न पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पुनः नियुक्त (Re-engagement) करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रेलवे बोर्ड के निर्देशों के तहत लिया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण नियम और शर्तें पात्रता मानदंड, आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 64 वर्ष और 6 महीने होनी चाहिए। पुनः नियुक्ति केवल 65 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगी। मान कैडर/श्रेणी से सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। उसी पे-लेवल से सेवानिवृत्त होने वाले उम्मीदवारों को उच्च पे-लेवल वालों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन एक नामित समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों के

APAR ग्रेडिंग (न्यूनतम 'Good'), कार्य अनुभव और सतर्कता क्लीयरेंस के आधार पर किया जाएगा। इस पुनः नियुक्ति के विभागों अनुसार पूर्ण विवरण पर बात करें, तो परिचालन विभाग के 12, वाणिज्य विभाग के लगभग 48, पर्सनल और सामान्य प्रशासन विभागों के लगभग 20 कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर 80 सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जम्मू श्री उचित सिंघल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का वर्षों का अनुभव और कार्य के प्रति उनकी निष्ठा जम्मू मंडल के सुचारु संचालन में मील का पत्थर साबित होगी। नई मंडल संरचना के तहत सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए अनुभवी कार्मिकों की पुनः नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी अपनी सेवाएं राष्ट्रहित में पुनः अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त होगा।”



ठाणे-मुलुंड के बीच नए उपनगरीय रेल स्टेशन को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

सूत्र/रे.स.ब्यू - रेल मंत्रालय ने ठाणे और मुलुंड के बीच नए उपनगरीय रेल स्टेशन के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को पत्र भेजकर स्वीकृति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सामाजिक माध्यमों पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रस्तावित स्टेशन मुंबई महानगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सक्षम और गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नया स्टेशन विशेष रूप से घोड़बंदर, पोखरण मार्ग तथा वागले औद्योगिक क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

आधिकारिक अनुमान के अनुसार, नए स्टेशन के निर्माण के बाद ठाणे रेल स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ में लगभग 31 प्रतिशत तथा मुलुंड रेल स्टेशन पर लगभग 24 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है। वर्तमान में ठाणे स्टेशन प्रतिदिन छह लाख से अधिक यात्रियों का भार वहन कर रहा है और यह मुंबई महानगर क्षेत्र के सबसे व्यस्त रेल स्टेशनों में शामिल है। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना उपनगरीय रेल तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी तथा यात्रियों को बेहतर संपर्क, सुगम आवागमन और अधिक सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराएगी।



संपादकीय

जहां संभव हो, रेलगाड़ी से यात्रा करें। ईंधन बचाएं, देश को मजबूत बनाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं

दुनिया इस समय ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण बड़े ऊर्जा संकट की आशंका से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार होर्मुज में तनाव और तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि यदि यह संघर्ष लंबा चला तो दुनिया भर में ईंधन संकट और महंगाई और बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। तेल महंगा होने का मतलब केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि परिवहन लागत, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में भी वृद्धि होना है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वह अपील और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, भारतीय रेल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत आधार भी है। एक ट्रेन हजारों यात्रियों को एक साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, जबकि उतने ही लोगों द्वारा अलग-अलग कारों का उपयोग करने पर ईंधन की खपत कई गुना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार रेल यात्रा निजी वाहनों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है। भारतीय रेल का बड़ा हिस्सा अब तेजी से विद्युतीकृत हो रहा है, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हुई है। यही कारण है कि आज रेल यात्रा केवल सुविधा नहीं, बल्कि देशहित में एक जिम्मेदार विकल्प बन चुकी है। देशभक्ति केवल नारों और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सच्चा राष्ट्रप्रेम हमारे रोजमर्रा के निर्णयों में दिखाई देना चाहिए। यदि हर नागरिक छोटी दूरी की यात्राओं में भी निजी कारों की बजाय रेल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना शुरू कर दे, तो करोड़ों लीटर ईंधन की बचत संभव है। इससे न केवल देश की विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी। आज जब दुनिया युद्ध और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है, तब हर भारतीय का छोटा-सा प्रयास भी देश के लिए बड़ा योगदान बन सकता है।

₹300 Crore Transformation: Brahmapur Railway Station Set for Modern Makeover with 3 New Lines and a Design Reflecting Southern Odisha's Spiritual and Cultural Heritage

Source/ECoR- Brahmapur Railway Station, the busiest rail hub of southern Odisha handling over 162 trains and 25,000 passengers every day, is set to undergo its most ambitious overhaul since its founding. East Coast Railway has sanctioned a ₹300 crore multi phase redevelopment that will fundamentally reshape how one of Odisha's most important cities connects with the rest of India.

New Lines & Platforms: A Capacity Leap- At the heart of the redevelopment is a major capacity expansion. The station will gain three additional railway lines and four new platforms, significantly enhancing its ability to handle the growing number of originating, terminating and passing trains. A new station building on the second entry side and extensive yard modifications are part of the same package. The project also includes relocation of the service building and railway quarters, freeing up space for a more passenger centric layout.

Seamless Connectivity- The redevelopment envisions a fully integrated passenger movement system that will ensure seamless connectivity across both sides of the station and all platforms. Unlike conventional arrangements, this elevated structure will facilitate continuous flow. The existing Foot Over Bridge is also being extended to further strengthen passenger movement and accessibility across the station.

Accessibility- The redeveloped station will feature adequate lifts and escalators, making it one of the most accessibility focused stations on the East Coast Railway network. Divyang friendly infrastructure, tactile pathways and level access facilities will be integrated throughout, ensuring inclusive and barrier free movement for all passengers.

Circulating Areas on Both Sides: The Dual Gateway- The redevelopment will address long standing congestion



issues by creating fully developed circulating areas on both sides of the station. The main circulating area improvements including road widening, footpaths, drainage, compound wall and landscaping have already been completed. The second entry circulating area is being developed, providing the city with an additional fully functional station gateway.

Platform Upgrades & Operational Efficiency- The project includes refurbishment of platform flooring and existing sheds, along with extension of cover sheds to provide enhanced weather protection. The installation of a Quick Watering System (QWS) will enable rapid and efficient watering of coaching rakes, reducing turnaround time and facilitating faster train departures. Additional platform shelters are also under construction.

Smart Station Features- The redevelopment incorporates modern systems including CCTV surveillance, access control, baggage scanners, passenger information systems and integrated electrical and signalling upgrades. Multilingual wayfinding signage in Odia, Hindi and English will enhance passenger convenience and navigation.



Ganjam's Pride, Brahmapur's Identity- The redevelopment of Brahmapur Railway Station marks a decisive alignment of modern infrastructure with the distinct identity of the region. Backed by strong local support, the project anchors the station in the cultural and spiritual fabric of the region and the rich heritage of southern Odisha.

As a key gateway, the station is being reimagined not just as a transit hub but as a landmark reflecting Brahmapur's tradition. on completion, it will stand as a compelling example of infrastructure shaped by regional identity while delivering a world class passenger experience.

South Coast Railway to Become India's 18th Railway Zone

Source/RSB- South Coast Railway is set to become India's 18th railway zone, with its head quarters located in Visakhapatnam and operations expected to begin from June 2026. The new zone has been formed by reorganising parts of the East Coast Railway and South Central Railway networks, addressing a long-standing demand from Andhra Pradesh. The development is expected to strengthen railway administration, improve operational efficiency, and enhance freight movement and port connectivity in the region. The formation of South Coast Railway is also aimed at supporting faster infrastructure development and streamlining rail operations across key industrial and coastal corridors.

New Chief Public Relations Officer for Southern Railway

Source/RSB - Shri S.N. Narain assumed charge as the Chief Public Relations Officer of Southern Railway on 13th of May 2026. Prior to this assignment, Shri S.N. Narain was serving as Private Secretary to the Hon'ble Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas & Tourism, on deputation. An officer of the Indian Railway Traffic Service (IRTS) from the 2010 batch, Shri S.N. Narain has held several important assignments in Indian Railways relating to passenger amenities, operational efficiency, digital communication and public interface. Shri S.N. Narain has served in various capacities in the Operations and Commercial wings across different Divisions of Southern Railway. Later, he proceeded on deputation to New Delhi working as Deputy Secretary in the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology and as Private Secretary to the Hon'ble Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas & Tourism. During his tenure in Southern Railway, he has held the posts of Senior Divisional Commercial Manager of Tiruchchirappalli Division, Deputy Chief Operations Manager (Traffic Safety), Southern Railway, Divisional Commercial Manager at Chennai and Palakkad Divisions, and Divisional Operations Manager at Salem Division, among others. He has also been associated with the implementation of several important projects and policy initiatives of Indian Railways. Shri S.N. Narain holds a degree in Mechanical Engineering from PSG College of Technology, Coimbatore. He succeeds Shri M. Senthamil Selvan who has now been posted as Senior Divisional Electrical Engineer, Royapuram Loco Shed.

Northern Railway leads its Operational Management with Technological Innovations and Enhanced Safety Measures

General Manager of Northern Railway, launched a YouTube Channel "RailSafe" to strengthen Safety

Source/NR A conference on Train Operations was organised at Baroda House, New Delhi on 06.05.2026. The event was graced by Shri Rajesh Kumar Pandey, General Manager of Northern Railway. Smt. Monica Agnihotri, Principal Chief Operations Manager (PCOM) and Sr. Divisional Operations Managers (Sr. DOMs) from all Divisions: Delhi, Ambala, Firozpur, Lucknow, Moradabad, and Jammu were also present at the conference. The conference offered a platform for senior leadership to review operational management collectively and overcome difficulties present at the ground level. Shri Rajesh Kumar Pandey, General Manager of Northern Railway, launched a YouTube Channel "RailSafe" to strengthen Safety, aimed at equipping operational staff with vital knowledge related to safe railway operations. The channel provides frontline employees with practical content that helps them in understanding and enhancing train operations. The General Manager emphasised that safety remains the priority of Northern Railway. The Sr. DOMs from their respective Divisions gave



elaborate reviews that highlighted the progress made on punctuality, freight loading, station management, and safety standards. All discussions were based on optimising the crew, strengthening monitoring, and improving last-mile connectivity for both passengers and freight. There was also a discussion on leveraging digital technologies to ensure timely decisions. Some Divisions of the Northern Railway have taken the lead in implementing technology-driven innovations that have helped in modernising field work and improved operations significantly, some of which were showcased in the conference.

AARAV: (Automated Monitoring, Alert & Real-Time Analysis Validation System)- The Operating Department of the Jammu Division has developed a mobile-based tool under its Station Working Group, enabling real-time field reporting. Officers can instantly log deficiencies, select the concerned department (e.g., Engineering, S&T, Commercial), and the system automatically maps the issue to the relevant Branch Officer and Supervisor for prompt action.

Delhi Division's Six-Point Safety Drive The Delhi Division has built safety through a 6-ground-level plan. It includes daily scrutiny of safety performance with the help of Nav Sanraksha. Weekly counselling sessions through Sanraksha Chaupal, with 856 staff covered so far, along with the live KPI Monitoring App, which monitors all 12 Sectional TIs, are enhancing operations. A mentor-mentee programme scheme that is another initiative that pairs junior staff with senior supervisors to bridge knowledge gaps. Digital Safety Posters on LED screens at key panel rooms keep safety messaging visible during duty hours. 61 Shunting Melas have taken conversations directly to the frontline workers.

Afcons forays in Europe, with a major railway project in Croatia



Source/RSB- Afcons Infrastructure has announced that it has been selected as the most suitable bidder for a major railway rehabilitation and construction project in Europe, marking the company's entry into the European infrastructure market. The project is set to become Afcons' largest international order to date and reflects the company's continued global expansion in delivering large-scale infrastructure projects.

Executive Chairman Mr. Krishnamurthy Subramanian stated that the project represents a significant milestone in Afcons' international journey and highlights the company's capability to execute complex infrastructure developments across geographies. He added that the project further strengthens Afcons' position as a trusted partner in global infrastructure development.

According to Managing Director Mr. S. Paramasivan, the project includes reconstruction of the existing railway track along with construction of a second railway line. The scope of work also covers overhead electrification, signalling, and telecommunication systems. The total project value stands at €677.07 million, excluding taxes. Afcons officials said the company is currently completing formal formalities related to the project and is preparing for mobilization and execution.

Siemens hands over first set of 9000 HP electric locomotives for commercial operations



Source/RSB- Indian Railways marked a significant milestone in India's rail freight modernization journey with the commencement of commercial operations of 9000 horsepower (HP) electric freight locomotives. Designed for heavy-haul freight operations, the D9 electric locomotives of 9000 HP represent one of the most powerful freight locomotives deployed in the world with speeds of up to 120 km/h. The commencement of commercial operations follows a record execution timeline, with the locomotives entering commercial operations within 36 months from the contract date, one of the fastest deliveries for a project of this scale in the Indian rail sector.

The project is being executed under a long-term availability-based lifecycle partnership model, covering the design, manufacturing, commissioning, and 35 years of full-service maintenance. Locomotives are being manufactured at the Indian Railways' factory in Dahod, Gujarat, while maintenance will be undertaken at depots in Visakhapatnam, Raipur, Kharagpur, and Pune, supporting sustained performance and high fleet availability.

Sunil Mathur, Managing Director and Chief Executive Officer, Siemens Limited, said, "This is a proud moment for Siemens as a long-standing and trusted partner of Indian Railways. The successful handover of the electric locomotives sets a new benchmark in rail modernization, enabled by a pioneering partnership and a robust lifecycle business model. It reflects the strength of collaboration between Indian Railways and Siemens and stands as a testament to the manufacturing and engineering excellence of the people who made this achievement possible, embodying the spirit of 'Viksit Bharat'."

Approximately 90% of the locomotive technologies are made in India, reinforcing Indian Railways' and Siemens' shared commitment to 'Make in India' and the development of a strong domestic rail manufacturing ecosystem. The project has also contributed to capability building across Indian suppliers, manufacturing facilities, and skilled talent.

The 9,000 HP electric locomotives are equipped with advanced digital systems, including Railigent X, Siemens' intelligent rail asset management platform, enabling predictive maintenance and data-driven performance optimization. The locomotives integrate advanced safety and monitoring technologies and are engineered for energy-efficient, high-reliability freight operations across the Indian Railways network. Over their lifecycle, the locomotives are expected to contribute significantly to sustainability outcomes supporting India's broader climate and logistics efficiency goals.

Indian Railways Launches AI Assistants 'Bholu Mini' and 'Bholu Max' at Telangana Stations

Source/IR&RSB - Indian Railways has introduced AI-powered assistants named 'Bholu Mini' and 'Bholu Max' at railway stations in Telangana, specifically at Malkajgiri and Kacheguda. These assistants provide passengers with real-time train and station information through both voice interaction and touchscreen interfaces. The systems are designed to support multiple languages, enabling a wider range of passengers to access information easily. By offering instant updates and user-friendly interaction, the initiative aims to improve convenience and enhance the overall travel experience for railway passengers.



Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Bridge Over Sabarmati River Reaches Key Construction Milestone



Source/IR&RSB- A 36-metre-tall and 480-metre-long bridge being constructed over the Sabarmati River in Gujarat for the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project has achieved significant progress. All foundation and substructure works for the bridge have been completed, marking an important step forward in the project's development.

The update highlights ongoing construction activity and reflects steady advancement in infrastructure work associated with the high-speed rail corridor. The completion of foundational stages indicates progress toward the next phases of construction, as work continues on the project.

DELHI METRO PARTNERS WITH AIRTEL PAYMENTS BANK TO LAUNCH CO-BRANDED RUPAY 'ON-THE-GO' NCMC CARDS

Source/DMRC- In a significant step towards advancing integrated urban mobility, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has partnered with Airtel Payments Bank to launch co-branded RuPay 'On-The-Go' Cards, enabled with NCMC (National Common Mobility Cards). These cards will enable seamless, interoperable payments across metro systems, buses & other transit networks nationwide. This announcement was made in a ceremony at the Delhi Metro headquarters attended by DMRC MD, Dr. Vikas Kumar, MD & CEO of Airtel Payments Bank Mr. Anubrata Biswas, and other senior officials from both the organisations. The co-branded cards – Debit cards and PPI-MTS (Prepaid Payment Instrument for Mass Transit Systems) Cards will allow commuters to pay for metro travel across multiple cities and transit systems using a single open-loop card. This represents a significant upgrade from existing DMRC issued cards, which are limited to the Delhi Metro network. The initiative is aligned with the Government of India's 'One Nation, One Card' vision, aimed at simplifying and unifying transit payments across the country.

The cards will be available at all DMRC stations in next 10 days, ensuring easy accessibility for commuters. In addition, users can recharge their cards digitally at any time through the DMRC app or the Airtel app, significantly reducing the need to queue at stations for top-ups.

Dr. Vikas Kumar, Managing Director, Delhi Metro Rail Corporation Ltd, said, "DMRC has consistently focused on adopting innovative solutions to enhance passenger convenience. This exclusive partnership with Airtel Payments Bank and the introduction of co-branded NCMC cards will enable seamless and interoperable travel for our commuters, not only



within the Delhi Metro network but also across multiple transit systems nationwide."

Mr. Anubrata Biswas, MD & CEO, Airtel Payments Bank, said, "Our partnership with DMRC reflects a shared vision to simplify and modernise urban mobility through secure, digital-first solutions. With the launch of the co-branded 'On-the-Go' NCMC cards, we are enabling commuters to experience seamless travel across transit systems, while advancing the larger ambition of 'One Nation, One Card' for India." Existing issued cards will continue to function as usual. DMRC will continue to further promote the sale of NCMC cards going forward.

SH SANJAY JAMUAR APPOINTED THE FIRST CEO OF DMIL

Source/RSB- Sh. Sanjay Jamuar has been appointed as the first Chief Executive Officer (CEO) of Delhi Metro International Limited (DMIL) which has been set up by DMRC with the support of the Government to take up Metro projects as well as Operation and Maintenance (O&M) assignments in India outside Delhi and abroad. DMIL has the mandate to offer advisory services to other authorities and lenders to help develop, improve and prepare long term plans for metro and transit systems. DMIL will leverage the experience and expertise of DMRC which has directly or indirectly helped many cities in India to build their own metro systems.

Sh. Jamuar is an ex IRTS officer with wide experience across the Indian railways, DMRC, and internationally in the UK, USA, France, Middle East and Europe. He holds a Post Graduate Diploma in strategic leadership from Warwick Business school UK, and has done research work at Leeds University in Transport Economics. Incidentally when he joined DMRC in 1998 he was the first O&M employee. Therefore, coming back to DMRC is like a homecoming for him.

DMRC is already involved as a consultant with the Dhaka Metro project in Bangladesh. It is also handling crucial O&M contracts for the Chennai, Mumbai and Patna Metro projects and has played the role of the consultant for almost all major Metro projects in India. DMRC has also carried out construction work for Metro projects in Mumbai, Jaipur and Patna. Therefore, the DMIL is now expected to further expand DMRC's footprint across the world.



RVNL Bags ₹221-Crore Rail Signalling Project in Chhattisgarh

Source/RSB- Rail Vikas Nigam Limited has secured a ₹221.3-crore EPC contract from South East Central Railway for railway infrastructure works in Chhattisgarh. The company emerged as the lowest bidder for the project, which will be carried out in the Bilaspur division. The project involves signalling and telecommunication upgrades aimed at enhancing railway operations and safety standards in the region. As per the report, the work is expected to be completed within a period of 730 days.



IRFC Receives Visionary Partnership Award at IIT Madras Technology Summit 2026

Indian Railway Finance Corporation has been honoured with the Visionary Partnership Award at the IITM Social Impact Awards 2026, held during the IIT Madras Technology Summit 2026. The recognition by Indian Institute of Technology Madras highlights IRFC's contribution towards creating meaningful social impact through technology-driven initiatives. The award acknowledges the organisation's support for patient capital aimed at promoting groundbreaking research and development through its CSR programmes. IRFC stated that it remains committed to strengthening last-mile access and supporting inclusive and sustainable growth through impactful initiatives across sectors.

RailTel Secures ₹145.47-Crore Connectivity Contract from Eastern Coalfields Limited

Source/RSB- RailTel Corporation of India has secured a ₹145.47-crore contract from Eastern Coalfields Limited for providing MPLS-VPN, Internet Leased Line (ILL), Video Conferencing (VC), and Managed Bandwidth Services (MBS). The project is aimed at strengthening communication infrastructure through secure, scalable, and high-availability network solutions for mission-critical operations. Under the contract, RailTel will enable seamless connectivity, high-speed internet access, and enhanced collaboration systems to support operational efficiency, real-time monitoring, and improved safety frameworks. The development further reinforces RailTel's growing role in delivering advanced digital connectivity solutions for critical infrastructure and industrial operations across the country.

Indian Railways Sanctions ₹362-Crore Kavach Expansion Across Northern Railway

Source/RSB- Indian Railways has approved expansion of the indigenous Kavach automatic train protection system across major Northern Railway routes with an investment of around ₹362 crore, strengthening efforts towards railway safety & network modernisation. The sanctioned project covers nearly 1,478 route kilometres across key sections of the Firozpur and Jammu divisions. As part of the plan, Kavach will be deployed over around 1,000 route kilometres in the remaining sections of the Firozpur Division at an estimated cost of approximately ₹241 crore. In the Jammu Division, the system will be installed on the Jalandhar City Junction–Jammu Tawi–Shri Mata Vaishno Devi Katra, Batala–Pathankot Junction, and Banihal–Baramulla routes, spanning nearly 466 route kilometres with an estimated outlay of about ₹121 crore.

Central Railway cracks down on misuse of Foreign Tourist Quota- 39 cases detected and Rs.3.56 lakh recovered as penalty

Source/RSB- Central Railway has intensified its drive against misuse of the Foreign Tourist (FT) Quota after detecting irregularities in bookings by Indian citizens traveling without valid supporting documents. The matter came to light in Train No. 12296 Sanghamitra Express on 04.02.2026, where certain Indian passengers were found travelling on FT Quota tickets without possessing the requisite documents mandated for foreign tourists. A detailed analysis of future-dated bookings under FT quota was undertaken. Scrutiny revealed that 174 originating PNRs of Central Railway were generated across 31 trains for the period 24.04.2026 to 11.06.2026 under the FT

quota. Special checks were conducted by CR Ticket Checking staff to verify the authenticity of FT quota tickets. During these drives, 39 PNRs were found booked through misuse of the FT quota.

A total of 121 passengers were detected travelling irregularly. They were charged as per extant rules and an amount of Rs.3,56,916/- was recovered as penalty. The passengers were not permitted to occupy the berths, which were subsequently allotted to RAC/Waitlisted passengers. Additional details have been sought from IRCTC to ascertain whether any authorized booking agents are involved in these bookings. Investigation is

underway to identify individuals and entities involved in unauthorized booking under the FT quota. Booking tickets under an ineligible quota is a punishable offence under The Railways Act., Passengers must carry valid ID and supporting documents as required for the quota under which the ticket is booked. Central Railway appeals to passengers to report / share any such information to the nearest on duty Railway personnel or on 139 or through the Rail Madad App. Central Railway also appeals to all passengers to ensure the correctness and validity of their tickets before undertaking travel.

Jammu-Srinagar Vande Bharat Express Services Serve Around 45,000 Passengers in First 10 Days of its Run



Source/RSB- On 30th April 2026, Union Railway Minister Shri Ashwini Vaishnaw flagged off the augmented, 20-coach Jammu Tawi-Srinagar Vande Bharat Express. Within just ten days of its regularisation date 2nd May, the 4 train services combined carried 44,727 passengers (up to 11th May) across both directions of travel, firmly establishing itself as the lifeline of Jammu and Kashmir. In the maiden week of its run itself, the train services hosted 28,762 passengers (up to 8th May).

The two pairs of Vande Bharat services operating on the corridor are Train No. 26401 (Jammu Tawi to Srinagar) and its return service Train No. 26402 (Srinagar to Jammu Tawi), which run six days a week except Tuesdays, and Train No. 26403 (Jammu Tawi to Srinagar) and its return Train No. 26404 (Srinagar to Jammu Tawi), which operate on all days except Wednesdays. Together, they ensure that the crucial Jammu–Kashmir corridor is served by 4 train services a day, at least five days a week. Each Tuesday and Wednesday, 2 train services also continuously serve the high-demand route, offering to-and-fro movement for locals, tourists, pilgrims, and traders alike.

A Week That Rewrote Expectations

Two pairs of Vande Bharat services now operate across the 266-km corridor, ensuring passengers at both ends have at least one, and on most days two, daily options. On days when both pairs ran, demand consistently pushed figures to near-capacity levels: 4,977 passengers on 3rd May, 4,955 on 8th May, 5,284 on 9th May, 5,657 on 10th May and 5,024 on 11th May. A train that earlier ran full with 8 coaches is now drawing near-capacity loads even with 20 coaches,

From Pilgrims to Traders, a Train for Everyone

These numbers represent more than ridership statistics. Pilgrims, students, government officials, and traders between Jammu and Srinagar travel without a break in journey for the first time. Tourists who once found the Valley logistically challenging now ride through the engineering marvels of the Chenab and Anji bridges from the comfort of a Vande Bharat seat. Crucially, the train is engineered to operate in temperatures as low as minus 20 degrees Celsius, making it a dependable all-weather artery when snowfall and landslides render the National Highway impassable for days at a stretch.

A Journey That Is Easier on the Pocket Too

The Vande Bharat is also the most affordable option on the corridor. A Chair Car ticket, meals included, costs a fraction of what a budget airline charges for the same journey, while even the cheapest one-way flight comes in at a significantly higher price. A shared cab per seat costs more, and a private taxi several times more still, with no protection against highway disruptions. The Jammu-Srinagar Vande Bharat does not merely connect two cities; it takes you through one of the most picturesque rail routes in the world. From the rugged terrain of Jammu, across the gravity-defying Chenab and Anji bridges, through tunnels carved into the Himalayan rock, and into the sunlit valleys of Kashmir, every kilometre of this journey is an experience in itself. Indian Railways has priced this extraordinary ride below its own cost of operations, a deliberate choice to ensure that a journey of this quality remains within every

passenger's reach. Paradise on Earth is no longer a privilege; it is a train ticket away. Do not miss the chance to travel this very special route.

Timed Perfectly for Kashmir's Golden Season
The Vande Bharat's extension coincides with the arrival of summer, the season when Kashmir truly earns its title of Paradise on Earth. As the valleys bloom, the Dal Lake shimmers, and the meadows of Pahalgam and Gulmarg beckon travellers from across the country, the timing of this service could not be more opportune. Tourists can now board at Jammu Tawi and arrive in Srinagar in under five hours, faster, cheaper, and more dependably than any alternative. The peak tourist months ahead are expected to push ridership well beyond the already impressive figures, and Indian Railways stands ready to meet that demand.

Special Commandos Deployed for Security of Jammu-Srinagar Vande Bharat Express

Source/RSB- Indian Railways has deployed special security arrangements for the Jammu-Srinagar Vande Bharat Express, with more than 21 security personnel, including RPF commandos known as CORAS, assigned to guard the train service. According to officials, a pilot vehicle will move ahead of the train as an additional security measure. Guard posts will also be stationed at intervals of every two kilometres along the route to strengthen surveillance and ensure passenger safety. The enhanced security deployment comes as part of efforts to provide safe and secure operations for the Vande Bharat service connecting Jammu and Srinagar.





मां गंगा-सा विस्तार, सुख-समृद्धि अपार गंगा एक्सप्रेसवे

मेरठ

प्रयागराज

हापुड़

प्रतापगढ़

बुलंदशहर

सायबरेली

अमरोहा

उन्नाव

सम्भल

बदायूं

शाहजहांपुर

हरदोई



₹36,230 करोड़

से निर्मित उत्तर प्रदेश के सबसे विराट
594 कि.मी. लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ-प्रयागराज) का

लोकार्पण
प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी

के द्वारा

सम्पन्न हुआ



विस्तार भी-रफ्तार भी : 6 लेन वाले (8 लेन में विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेसवे से 12 जनपद आच्छादित
● डिजाइन स्पीड 120 कि.मी./घंटा, मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 से 8 घंटे में होगी पूरी ● हापुड़ में गंगा नदी पर 960 मीटर एवं बदायूं में रामगंगा नदी पर 720 मीटर का दीर्घ सेतु ● मेरठ एवं प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा सहित कुल 21 रैम्प इंटरचेंज ● पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम ● लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग एवं टेक-ऑफ हेतु शाहजहांपुर के समीप 3.50 कि.मी. लम्बी हवाई पट्टी ● एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 3.75 मी. चौड़ी स्टेजर्ड सर्विस लेन

विकास भी-कल्याण भी : फ्यूल एवं ई-चार्जिंग सुविधा के साथ 9 विशाल जन-सुविधा परिसर
● गंगा एक्सप्रेसवे के 12 जनपदों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास का कार्य गतिमान ● औद्योगिक इकाइयों एवं कृषि उत्पादन क्षेत्रों की दिल्ली से तीव्र कनेक्टिविटी ● कृषि, वाणिज्य, पर्यटन एवं औद्योगिक आय में होगी वृद्धि ● दुग्ध, सब्जी, फल के भंडारण एवं प्रसंस्करण के नवीन केंद्र खुलेंगे ● व्यापार एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा ● नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण एवं मेडिकल संस्थानों के लिए असीम संभावनाएं

/ गरिमामयी उपस्थिति /

आनंदीबेन पटेल **योगी आदित्यनाथ**

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

पंकज चौधरी
राज्य मंत्री, वित्त,
भारत सरकार

जितिन प्रसाद
राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी,
वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार

केशव प्रसाद मोर्य
उप मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य,
उत्तर प्रदेश

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
मंत्री, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन,
एन.आर.आई. तथा निवेश प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश

एवं अन्य गणमान्य महानुभाव



दिनांक : 29 अप्रैल, 2026 | स्थान : मल्लावां कट, निकट चैनैज 351 कि.मी. गंगा एक्सप्रेसवे, तहसील - बिलग्राम, जनपद - हरदोई, उ.प्र.

सुपरफास्ट प्रदेश- उत्तर प्रदेश : 8 एक्सप्रेसवे संचालित, 14 विकास के विभिन्न चरणों में ● देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% भाग उत्तर प्रदेश में मौजूद ● एक्सप्रेसवे के आसपास 26 जनपदों के 27 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ● औद्योगिक विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का क्रियान्वयन ● पीएम गति शक्ति को लागू करने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश ● अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज एवं आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापना का कार्य गतिमान ● ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी (उत्तर प्रदेश) में स्थित ● देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में (16,000 किलोमीटर) ● 17 एयरपोर्ट संचालित (5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट), 7 विकास के विभिन्न चरणों में ● राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी-हल्दिया) के अयोध्या तक विस्तार का कार्य प्रगति पर

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश



UPGovtOfficial

CMOUPPradesh

CMOUPPradesh